



**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**



कोरोना से जंग

संकलनकर्ता

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन



अजित कुमार सिंह



**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

  @spmrfoundation

Phone:011-23005850

अप्रैल 2020

विषय सूची

1. कोविड-19 : आजीविका संकट में रामबाण बना डीबीटी - शिवानन्द द्विवेदी 6
2. समय रहते लॉकडाउन के कारण ही आज अधिक जांच के बावजूद भारत में कोरोना के मामले कम हैं - सतीश सिंह 8
3. कोरोना से लड़ाई में विश्व के सबसे बेहतर नेता सिद्ध हो रहे मोदी - बी. एम. सिंह 10
4. लॉकडाउन के बावजूद सप्लाई चेन को मजबूत रखने में सफल रही है मोदी सरकार - प्रह्लाद सबनानी 11
5. कोरोना संकट से निपटने को देश सेवा में जुटी भाजपा - शिवप्रकाश 14
6. संकट की इस घड़ी में हर तरह से देश के नागरिकों के साथ खड़ी है मोदी सरकार - नवोदित सक्तावत 16
7. कोरोना महामारी से भारत की लड़ाई दुनिया के लिए विस्मय और प्रेरणा का विषय बन चुकी है - प्रणय कुमार 18
8. दवा उद्योग के क्षेत्र में विकसित देश भी अब भारत पर निर्भर - प्रह्लाद सबनानी 21
9. Stealing Grains – PDS Scam and TMC’s Politics of Pandemics in West Bengal - Dr. Anirban Ganguly 24
10. विपक्ष कुछ भी दलील दे, कोविड के खिलाफ लड़ाई में आंकड़े मोदी सरकार की सफलता की ओर ही इशारा करते हैं - शिवानन्द द्विवेदी 29
11. कोरोना से संघर्ष में योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध किया है कि वे वास्तव में कर्मयोगी हैं - बी. एम. सिंह 31
12. जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा, तब कांग्रेस केंद्र सरकार से लड़ रही है - रमेश कुमार दुबे 33
13. बेहतर एवं सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के चलते मेडिकल टूरिज्म का हब बनने की ओर बढ़ता भारत - प्रह्लाद सबनानी 34
14. कोरोना संकट के इस कठिन काल से और मजबूत होकर निकलेगा भारत! - पीयूष द्विवेदी 36
15. कोरोना संकट : मोदी के जिन कार्यों की विश्व प्रशंसा कर रहा, कांग्रेस उनमें खोटा निकालने में लगी है - आदर्श तिवारी 38

16. कोरोना संकट : डॉ. मोहन भागवत ने अपने संबोधन में दिखाई नई राहें - संजय द्विवेदी 41
17. कोरोना संकट : प्रधानमंत्री के सार्थक आह्वान पर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति - सुयश मिश्रा 42
18. संघ प्रमुख के उद्बोधन के निहितार्थ बहुत गहरे हैं - आदर्श तिवारी 45
19. कोरोना संकट की रोकथाम के लिए सभी मोर्चों पर तत्परतापूर्वक कदम उठा रही सरकार - रमेश कुमार दुबे 47
20. कोरोना, संवेदना और शिवराज : राजसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की हो रही पहल - संजय द्विवेदी 49
21. कोरोना के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का प्रदर्शन हमारी एकता तो दिखाएगा ही, मनोबल भी बढ़ाएगा - डॉ दिलीप अग्निहोत्री 51
22. जनता कर्पूर्युः यह कोरोना से बचाव ही नहीं, आपदा में देश की एकजुटता का प्रमाण भी है - नवोदित सक्तावत 53
23. कोरोना काल में ममता की संकीर्ण राजनीति का शिकार बंगाल - डॉ रवि प्रभात 55
24. तीन मोर्चों पर कोरोना से लड़ रही मोदी सरकार, नागरिकों की भी है बड़ी जिम्मेदारी - डॉ दिलीप अग्निहोत्री 58
25. दिल्ली से मजदूरों के पलायन के लिए जिम्मेदार है केजरीवाल सरकार - आदर्श तिवारी 60
26. कोरोना से लड़ाई में फ़ेक न्यूज़ फैलाने में जुटे वैचारिक गिरोह से सावधान रहने की जरूरत - अनुराग सिंह 62
27. क्यों दिल्ली से मुंबई तक पलायन के नाम पर जुटी भीड़ के पीछे साज़िश प्रतीत होती है? - प्रणय कुमार 64
28. एफडीआई नियमों में ताजा बदलाव से होगी भारतीय हितधारकों की रक्षा - सतीश सिंह 67
29. कोरोना आपदा ने समझाया कि क्यों जरूरी है नागरिकों का डाटाबेस - रमेश कुमार दुबे 69
30. कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव से बची रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था - प्रह्लाद सबनानी 71
31. कोरोना राहत पैकेज : लॉकडाउन में गरीबों और अर्थव्यवस्था के हितों को सुरक्षित रखने की पहल - सतीश सिंह 73
32. Mamata plays politics of pandemic - Dr. Anirban Ganguly 75

भूमिका

को रोना महामारी के संकट से देश जूझ रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के कारण आज विश्व में हमारी स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा एक के बाद एक कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। मसलन देशवासियों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का निर्णय हो अथवा इससे उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करना हो। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर कुशल रणनीति का परिचय दिया है। आज देशभर में कोरोना पर ही चर्चा हो रही है। इसी के मद्देनजर वैचारिक वेब पोर्टल नेशनलिस्ट ऑनलाइन ने देशभर के कई वरिष्ठ पत्रकारों, लेखकों एवं शोधार्थियों द्वारा कोरोना के विभिन्न पहलुओं पर आलेख लिखवाए एवं प्रकाशित किया। पोर्टल पर प्रकाशित तमाम आलेखों को संकलित करके एक ई-बुकलेट के माध्यम से पाठकों तक इस विषय से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन इस ई-बुकलेट का प्रकाशन कर रहा है।

कोविड-19 : आजीविका संकट में रामबाण बना डीबीटी

► शिवाणन्द द्विवेदी

वैश्विक स्तर पर उभरे कोविड-19 संकट की चुनौतियों से देश दोतरफा जूझ रहा है शहरी आबादी के सामने कोविड से बचाव व पलायन की वजह से पैदा हो रही परिस्थिति से निपटने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत के सामने आजीविका के सुरक्षा का सवाल है। भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है तथा उसकी आजीविका निर्भरता भी श्रम संबंधी उपक्रमों पर टिकी है। ऐसे में जब लॉक डाउन की वजह से श्रम के अवसर कम हो गये हैं, तब शहरों के साथ-साथ गांवों में आजीविका और नकदी का संकट पैदा होना स्वाभाविक है। यह संकट लॉक डाउन की स्थिति में आम जन के धैर्य व भरोसे को भी डिगा सकता है। लगभग एक महीने के संपूर्ण लॉक डाउन के बावजूद ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण हैं।

हम यह तो नहीं कह सकते कि स्थितियां एकदम आदर्श हैं। वाकई स्थिति आदर्श नहीं बल्कि संकट वाली है। किंतु इस स्थिति को संभालने के प्रयास जमीनी स्तर पर बहुत हद तक कारगर जरूर नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी का संकट न हो तथा गरीब तबके को फौरी तौर पर राहत मिले, इसके उपाय सरकार द्वारा कुछ स्तरों पर किये गये हैं। नकदी के संकट की वजह से उभरने वाले असंतोष को रोकने में सरकार इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नकदी सहायता देने का प्रयास बहुतायत सफल

हुआ है। इस सफलता के पीछे सबसे कारण 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' के तहत जनहित की योजनाओं की मजबूत संरचना का तैयार होना है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रयी में कुछ साल पहले मोदी सरकार द्वारा जनहित के लिए पारदर्शी मॉडल दिया गया। यद्यपि जनधन से लगाये आधार तक को लेकर सरकार पर सवाल उठे और मखौल भी उड़ाया गया। किंतु वर्तमान के इस कठिन समय में 'जैम' की उपयोगिता उस निर्णय की दूरगामी दृष्टि को सही साबित करती है।

महाभारत में एक श्लोक है- स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद् यल्लोकहितं भवेत् अर्थात् राजा को अपने प्रिय लगने वाले कार्य की बजाय वही कार्य करना चाहिए जिसमें सबका हित हो। आज के सन्दर्भ में 'सबका हित' का आशय 'जनहित' के लिए कार्यों की पारदर्शिता से है। अस्सी के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस समस्या को कुछ इसतरह कहकर रेखांकित किया था कि 'एक रूपये भेजते हैं तो गांवों तक पंद्रह पैसे ही पहुँचते हैं।' मोदी सरकार द्वारा लाई गयी 'जनधन-आधार-मोबाइल' त्रयी ने दशकों पुरानी इस समस्या के लिए समाधान का कारगर रास्ता दिखाया है। महज चार वर्षों में देश के 56 विभागों की 427 योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के तहत 2 लाख 78 हजार करोड़ रूपये से अधिक का लाभ सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाना, एक बड़ी कामयाबी

है। जिस गति से भारत ने इस लक्ष्य को हासिल किया है, वह चमत्कारिक लगता है। किंतु बारीकी से देखें तो इसके पीछे योजनाबद्ध तैयारियों की मजबूत संरचना नजर आती है। डिजिटल इंडिया को ग्रामीण भारत तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने, गरीब से गरीब को मुख्यधारा के अर्थतंत्र से जोड़ने के लिए जनधन खाते खुलवाने, आधार से उनकी पहचान तय करने तथा बैंकिंग की पहुंच उन तक सुनिश्चित करने की योजनाबद्ध कार्यनीति ने आज देश को इस स्थिति में पहुंचाया है कि वह कोविड जैसी कठिन परिस्थिति में भी अपने नागरिकों को उनका राहत लाभांश सीधे उनके खाते में दे पा रहा है।

ग्रामीण जनजीवन में नकदी का संकट न हो तथा बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें आर्थिक तंगी का शिकार न होना पड़े, इसके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं है। केवल कोविड-19 के मद्देनजर खेतिहर मजदूरों के लिए सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत लगभग 18000 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से राहत पैकेज के तहत दी, जिससे लगभग 8.69 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की सब्सिडी का बकाया पैसा भी बिना किसी अवरोध के लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। देश के लगभग हर गांव में कुछ न कुछ परिवार ऐसे हैं जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। ऐसे लगभग 2.66 करोड़ परिवारों को अबतक तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलिंडर की उपलब्धता ने आजीविका के संकट से जूझने वाले परिवारों को राहत देने का काम किया है।

लॉक डाउन के दौरान कामकाज बंद होने से मनरेगा

मजदूरों के लिए भी स्थिति दयनीय हो सकती थी, लेकिन डीबीटी के तहत पुराने बकाये का भुगतान करके मोदी सरकार ने करोड़ों जॉब-कार्ड धारक मजदूरों के लिए राज्यों के माध्यम से राहत पहुंचाई है।

हालांकि कल्याणकारी राज्य में यह सब तो सरकार को करना ही होता है। इस लिहाज महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सरकार ने जनहित में यह कदम उठाये हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार द्वारा ऐसी विकट परिस्थिति के दौर से लड़ने तथा लक्ष्यावधि में इसे करने की सुदृढ़ संरचना तैयार की गयी है। कल्पना करिए यदि डीबीटी की संरचना नहीं होती तो क्या संभव था कि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभांश लोगों को सीधे पारदर्शी तरीके से मिल पाता ? शायद नहीं मिल पाता। अगर नहीं मिल पाता तो आज देश की स्थिति क्या होती, इसकी सहज कल्पना नहीं की जा सकती है। आज देश में जनभागीदारी और जनसहयोग की सफलता इसीलिए संभव है क्योंकि जनता को सरकार से जोड़ने के बीच की कड़ी भी पारदर्शी हुई है। अब सरकार जनता को जो देना चाहती है, उसके बीच कोई तीसरी कड़ी न के बराबर बची है। कठिन दौर के बावजूद उससे उबरने तथा जनता के बीच लोकप्रियता की कसौटी पर मोदी सरकार के खरा होने साबित होने के पीछे पारदर्शी शासन के नवाचारी मॉडल पर लगातार काम करना बड़ा कारण है। आज भी अगर जनता इतने लंबे समय तक लॉक डाउन का साथ दे रही है, तो इसके पीछे भी मूल कारण यही है।

(यह लेख पूर्व में प्रभात खबर में प्रकाशित है।)

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं।)

समय रहते लॉकडाउन के कारण ही आज अधिक जांच के बावजूद भारत में कोरोना के मामले कम हैं

► सतीश सिंह

को रोगा मानव अस्तित्व के लिये आज एक बड़ा खतरा बन गया है, जिससे बचने के उपाय फिलहाल बहुत ही कम दिख रहे हैं। सुधारात्मक उपायों को देर से अमलीजामा पहनाने वाले देशों को धीरे-धीरे यह अपनी चपेट में ले रहा है। चूंकि, फिलहाल इस रोग की कोई दवा नहीं है, इसलिये इसके रोकथाम के लिये जरूरी है कि देशव्यापी लॉकडाउन किया जाये साथ ही साथ संभावित मरीजों की अधिक-से-अधिक संख्या में टेस्ट किए जाएं और कोरोना से संक्रमित मरीजों को तुरंत 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा जाये। इस तरीके से ही संक्रमित और स्वस्थ लोगों को अलग किया जा सकता है।

इस तरीके को अपनाने से कोरोना महामारी को दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार जरूर कुछ समय तक के लिये कोरोना से होने वाली बड़ी संख्या में मौतों को टाल सकती है। भारत समेत विश्व के अनेक देशों को उम्मीद है कि वैज्ञानिक जल्द ही इस महामारी का टीका और दवा ढूंढने में कामयाब होंगे। विश्व के अनेक देशों के वैज्ञानिक इस बीमारी का समाधान निकालने के लिये विगत महीनों से निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं।

कोरोना से बचने के लिये भारत में समय रहते सरकार ने लॉकडाउन की नीति अपना ली जिस कारण आज भारत

की स्थिति उसकी विशाल जनसंख्या के बावजूद अन्य देशों से बेहतर है। इस बात की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। 16 अप्रैल तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पश्चिमी देशों के मुकाबले कोरोना के काफी कम मरीज हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन से पहले 3 दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे थे, अब कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने में औसतन 6.2 दिनों का समय लग रहा है।

देश के 19 राज्यों में यह अवधि और भी ज्यादा है। इन राज्यों में केरल, असम, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो लोग कोरोना से जंग हार रहे हैं उनमें से अधिकांश की उम्र 63 साल से अधिक है। इस उम्र वाले लोग अमूमन पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं।

एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि देश में कोरोना की जांच कम हो रही है जिससे मामले कम आ रहे, लेकिन लोगों की यह धारणा गलत है, क्योंकि भारत में स्क्रीनिंग काफी तेज रफ्तार से की जा रही है, लेकिन कोरोना के लक्षण मिलने पर ही संभावित मरीजों की जांच की जाती है। उदाहरण के तौर पर बिहार के 38 जिलों में 2 दिनों (16

एवं 17 अप्रैल) के अंदर 48 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।

जानकारी के अभाव में लोग यह भी कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जंग में जापान भारत से आगे है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। भारत में 24 लोगों की जांच पर एक मरीज निकल रहा है, जबकि जापान में 11.7, इटली में 6.7, अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में 3.4 जांच करने पर एक मरीज मिल रहा है। इस तरह मरीजों की संख्या के हिसाब से भारत दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना अधिक टेस्ट कर रहा है। भारत में कोरोना से मिलते-जुलते दूसरे संक्रमण वाली बीमारियों जैसे, सर्दी, खांसी, साँस लेने में तकलीफ आदि से ग्रसित मरीजों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है।

भारत में कोरोना के संक्रमण की गति को कम करने में सरकार को सफलता मिली है। भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर कोरोना के 9 मरीज मिले हैं, जबकि इसका वैश्विक औसत 267 मरीजों का है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लॉकडाउन को अमलीजामा पहनाने की वजह से ही देश के 736 जिलों में से 325 जिले कोरोना के प्रकोप से मुक्त हैं। देश में 28 जिले ऐसे भी हैं, जहाँ पहले कोरोना के मरीज थे, लेकिन विगत 14 दिनों से कोई कोरोना का नया मरीज नहीं आया है। इतना ही नहीं, भारत अभी भी कोरोना के सामुदायिक संक्रमण से बचा हुआ है।

भारत में कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावनाओं के संबंध में ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म प्रोटिविटी और टाइम्स नेटवर्क ने भी एक अध्ययन किया है, जिसके निहितार्थ बेहद ही सकारात्मक हैं। टाइम्स फैक्ट-इण्डिया-आउटब्रेक की रिपोर्ट, जो 16 अप्रैल को जारी की गई है, में कहा गया है कि भारत में मई महीने के तीसरे सप्ताह तक ही

कोरोना वायरस का प्रभाव रहेगा। उसके बाद यह कमजोर पड़ने लगेगा। इस अध्ययन में 8 राज्यों, देश के शीर्ष 3 हॉट स्पॉट्स, स्वास्थ्य मंत्रालय का दैनिक बुलेटिन, विदेशों में कोरोना के बढ़ने की प्रवृत्ति आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

कहा जा सकता है कि कोरोना के बारे में अभी भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, जिसमें पढ़े-लिखे लोग भी शामिल हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मौजूदा समय में जरूरत यह है कि हम कस्बाई, गाँवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस आपदा के बारे में बतायें और जागरूक करें। वर्तमान में सिर्फ सावधानी बरतकर ही हम कोरोना की धार को कुंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज फ़िलहाल किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है।

अभी कोरोना से ग्रसित वैसे ही मरीज ठीक हो रहे हैं जिनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की बेहतर प्रतिरोधक क्षमता है। हालाँकि, कोरोना के मरीजों को मलेरिया आदि की दवाइयां प्रयोग के तौर पर दी जा रही हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ठीक होने वाले कोरोना के मरीज दी गई दवाइयों से ठीक हुए हैं या अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण। इसलिये, मौजूदा समय में हम सभी लॉकडाउन का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें, इसी में हमारी और देश की बेहतरी है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, नागरिक के रूप में हमें भी नियमों का पालन कर उसका सहयोग करते रहने की आवश्यकता है। इसी तरह यह लड़ाई जीती जा सकती है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना से लड़ाई में विश्व के सबसे बेहतर नेता सिद्ध हो रहे मोदी

► बी. एम. सिंह

पूरी दुनिया पहली बार विषाणुजनित महामारी के बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। अमेरिका और चीन जैसे देश पस्त हो चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नजर एक ही शख्स पर है। लोग उम्मीद लगाये बैठे थे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महामारी से कैसे निपटते हैं।

संतोषजनक है कि मोदी अबतक इस विषय में एकदम सजग और तत्परतापूर्वक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं। उनके नेतृत्व में न केवल भारत खुद इस महामारी का बेहतर ढंग से सामना कर रहा है बल्कि दुनिया के अन्य देशों की सहायता भी कर रहा है। कहना गलत नहीं लगता कि इस मोर्चे पर मोदी दुनिया के सबसे बेहतर नेता सिद्ध हो रहे हैं।

आंतरिक मोर्चे पर नरेन्द्र मोदी के सामने चुनौती थी कि कैसे आम लोगों तक कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति को पैदा होने से रोका जाए। इसके लिए जनता से घर में रहने की अपील की गई। आईडिया क्लिक कर गया। लॉकडाउन की अपील को भारत की जनता ने सर माथे पर लिया और वही किया जिसकी जनता से उम्मीद थी।

इस तरह का प्रयोग भारत जैसे देश में, जिसकी आबादी 130 करोड़ के करीब है, के लिए बिलकुल नया था। लेकिन इसके कारण ही अबतक देश में कोरोना

अपना भयावह रूप नहीं ले सका है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी भारत के लॉकडाउन को सौ प्रतिशत कामयाब बताया है।

इस कठिन समय में लोगों का मनोबल कमजोर न हो और वे निराशा व अवसाद का शिकार न हो जाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कभी थाली-घंटी बजाकर कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने तो कभी प्रकाश करके अपनी राष्ट्रीय एकता दिखाने जैसे आह्वान किए जिसका असर देश भर में देखने को मिला।

अमेरिका, जो दुनिया की महाशक्ति है, उसके सामने समस्या थी कि भारत उसे जीवन रक्षक दवाइयों की खेप दे। इस पशोपेश में मोदी ने जो फैसला किया वह अपने आप में कमाल का था। उन्होंने न सिर्फ लोगों की जान बचने के लिए न सिर्फ अमेरिका को अपितु दुनिया के कम कम से पचास देशों में दवाई की खेप पहुंचवाई।

कहा जाता है कि संकट की स्थिति में ही नेतृत्व की पहचान होती है, पीएम मोदी ने न सिर्फ इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया बल्कि जनता के अन्दर भी इस तरह की भावना पैदा की, कि वह अपने घर-परिवार के साथ-साथ समाज और देश की भी सोचे। इसी सोच का नतीजा है कि कोरोना संकट से लड़ने में मोदी की हर आवाज़ पर देश की जनता उनके साथ खड़ी है।

जिन्होंने मोदी के इस स्वरूप को पहली बार देखा है, उनको अचरज हो सकता है लेकिन इस भूमिका की नींव तो बहुत पहले 2001 में पड़ गई थी जब गुजरात के विनाशकारी भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की मौत और कम से कम 2 लाख लोग घायल हुए थे। मोदी गुजरात के नए-नए मुख्यमंत्री बने थे और उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, कच्छ और भुज के पुनर्निर्माण की।

जिन्होंने पहले का भुज देखा होगा और आज का भुज देखा है, उनको अंदाजा होगा कि इस नये शहर को फिर से खड़ा करना कितना मुश्किल काम था। इस विनाशकारी भूकंप ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर

दिया था लेकिन इन चुनौतियों को नरेन्द्र मोदी ने एक अवसर के रूप में लिया और पूरे गुजरात का कायाकल्प कर दिया।

मोदी के सामने इस बार का संकट कहीं ज्यादा व्यापक है लेकिन चुनौती लेने का जज्बा न पहले कम था न आज कम हुआ है। पीछे मुड़कर देखने का प्रश्न ही नहीं जब देश की जनता खुद प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो। सरकार और जनता के बीच ये परस्पर सहयोग ही कोरोना के विरुद्ध देश की जीत की इबारत लिखेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

लॉकडाउन के बावजूद सप्लाई चेन को मज़बूत रखने में सफल रही है मोदी सरकार

▶ प्रह्लाद सबनानी

पूरे विश्व में फैली कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत में इस महामारी को रोकने के उद्देश्य से पहले इक्कीस दिन और फिर उन्नीस दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है जिसके चलते देश भर की अधिकतर उत्पादन इकाइयाँ बंद कर दी गईं एवं आर्थिक गतिविधियों सहित विभिन्न अन्य सामान्य प्रकार की गतिविधियों को भी रोक दिया गया।

इसके कारण सब्जी एवं फलों के सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ा। इस सबके चलते पूरे देश के विभिन्न भागों में जनता को ज़रूरी राशन सामग्री एवं दवाईयाँ पहुँचाने की

महती ज़िम्मेदारी सरकार के कंधों पर आ गई। केंद्र सरकार ने देश में सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने में सफलता पाई है जिसके कारण देश के किसी भी भाग में राशन सामग्री एवं दवाईयों की लेशमात्र भी कमी देखने में नहीं आई है एवं इन वस्तुओं की क्रीमतें भी नियंत्रण में बनी रही हैं।

जब लॉक डाउन की घोषणा की गई थी तब शुरू शुरू में ज़रूर कुछ समय तक सप्लाई चैन पर दबाव आया था। क्योंकि विनिर्माण इकाइयों के श्रमिक शहरों से अपने गावों की ओर पलायन कर गए थे। परंतु, शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर लिया गया। क्रीमतों पर भी

लगातार नज़र बनाए रखी गई जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं एवं दवाईयों के दाम नियंत्रित रहे।

आवश्यक राशन सामग्री एवं फल सब्जियाँ भी समय पर लोगों तक पहुँचाई गईं। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को समय पर बाज़ार पहुँचाने के उद्देश्य से सही समय पर देश के उन भागों में मंडियां प्रारम्भ कर दी गईं जहाँ कोरोना वायरस का शून्य अथवा कम प्रभाव था। अभी तक देश में 1600 से अधिक मंडियाँ खोली जा चुकी हैं। टमाटर, आलू, प्याज़, अन्य सब्जियों एवं फलों आदि की आपूर्ति को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की गई है। स्थिति को लगातार नियंत्रण में बनाए रखने में सफलता प्राप्त हुई है।

यूँ तो देश में ज़रूरी राशन सामग्री, फलों एवं सब्जियों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, परंतु फिर भी केंद्र सरकार ने सही समय पर इन वस्तुओं का उत्पादन एवं प्रसंस्करण करने वाली इकाईयों को प्रारम्भ करने की इजाज़त दे दी ताकि देश में इन उत्पादों की बिल्कुल कमी नहीं हो पाए एवं आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति लगातार देश में बनी रहे तथा इन पदार्थों की कीमतें न बढ़ पाएँ।

देश में एफएमसीजी क्षेत्र में खाद्य सामग्री आधारित 50 से 70 के बीच बड़ी कम्पनियाँ, ई-कामर्स कम्पनियाँ एवं व्यापार से व्यापार (बीटूबी) करने वाली कम्पनियाँ हैं जो सप्लाइ चैन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। लॉक डाउन के कारण इन कम्पनियों का उत्पादन घटकर 20/25 प्रतिशत होने लगा था, परंतु केंद्र सरकार इन कम्पनियों से लगातार सम्पर्क बनाए रही ताकि इनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को पुनः बढ़ाया जा सके।

हालाँकि इन कम्पनियों के सामने भी चुनौतियाँ कम नहीं थीं। इन कम्पनियों में कार्य करने वाले श्रमिक शहरों से गावों की ओर पलायन कर चुके थे। परंतु, उत्पादन इकाईयों के आस पास निवास कर रहे श्रमिकों को काम

पर बुलाकर इन कम्पनियों ने उत्पादन पुनः प्रारम्भ कर दिया।

केंद्र सरकार ने इन श्रमिकों को ई-पास जारी करने की प्रणाली प्रारम्भ कर दी। ताकि इस तरह के श्रमिकों को उत्पादन इकाई एवं इनके घरों से आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। केंद्र सरकार ने उत्पादकों, वितरकों, डिपो के मालिकों, परिवहन क्षेत्र के लोगों, थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं आदि का सहयोग प्राप्त किया। सरकार लगातार इनके सम्पर्क में बनी रही और इन सभी में सामंजस्य बिठाने का लगातार प्रयास किया। केंद्र सरकार लगातार पूरी सक्रियता से कार्य करती रही है।

यातायात वाहनों, विशेष रूप से ट्रकों, का सुरक्षा के साथ देश के विभिन्न भागों में आवागमन जारी रखा गया है। इसी प्रकार श्रमिकों के लिए विशेष वाहनों, बसों आदि की व्यवस्था भी की जाती रही ताकि उन्हें गावों से विनिर्माण इकाईयों की ओर आसानी से लाया जा सके। श्रमिकों के रहने की व्यवस्था भी विनिर्माण इकाईयों के आस पास करने का प्रयास भी किया गया है। यह सब लॉक डाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है।

भारत में कृषि क्षेत्र भी एक अहम क्षेत्र है। किसानों को खड़ी फ़सल काटने की अनुमति भी सही समय पर दे दी गई। काटी गई फ़सल को गोदामों में पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई है। मंडियाँ भी खोल दी गईं ताकि काटी गई फ़सलों को किसानों द्वारा बेचा जा सके। अभी देश में 544 लाख टन अनाज सरकारी गोदामों में उपलब्ध है। देश में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त है। दालें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नई फ़सल गेहूँ, सरसों, चना आदि की कटाई हो रही है और लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक कटाई सम्पन्न हो चुकी है। इसे बाज़ार में भी लाया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी ख़रीद प्रारम्भ कर दी है।

इस बार देश के कुछ गावों में फ़सलों की कटाई कार सेवा की तर्ज पर हुई है। गाँव के सभी किसानों ने मिलकर एक दूसरे के खेत पर खाड़ी फ़सल को काटा है। हालाँकि देश में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों द्वारा फ़सल कटाई के लिए मशीनों का उपयोग किस प्रकार करना है ताकि लॉक डाउन के नियमों का पालन भी किया जा सके एवं सामाजिक दूरी भी बनाए रखी जा सके। कृषि मंत्रालय ने इस सम्बंध में मानक परिचालन प्रक्रिया बनाई है। यह कृषि मंत्रालय की वेब साइट पर उपलब्ध है।

ज़िला प्रशासन भी इस सम्बंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाईयों के लिए उनके श्रमिकों को इन इकाईयों तक पहुँचाने हेतु आसानी से अनुमति दी जा रही है। हाँ, सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान भी रखा जा रहा है। देश में कई ऑटो कम्पनियों ने भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। ज़रूरी वस्तुएँ सब जगह लगातार मिल रही हैं। देश में पूरा सरकारी तंत्र एवं निजी संस्थान भी लगे हुए हैं ताकि देश में घबड़ाहट की स्थिति निर्मित नहीं हो और देश में ज़रूरी सामान की निर्बाध रूप से आपूर्ति बनी रहे।

राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में लॉक डाउन के लागू रहने के बावजूद, मध्य प्रदेश में अब तक 98-99 प्रतिशत गेहूँ की कटाई की जा चुकी है। इसी प्रकार राजस्थान में 92-95 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 85-88 प्रतिशत, हरियाणा में 55-60 प्रतिशत, पंजाब में 60-65 प्रतिशत एवं अन्य राज्यों में 87-88 प्रतिशत गेहूँ की कटाई सम्पन्न हो चुकी है। यहाँ यह जानकर खुशी होती है कि ग्रामीण इलाकों में

भी किसानों ने सामान्य तौर पर लॉक डाउन के नियमों का पालन करने का भरपूर प्रयास किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई एक अन्य जानकारी के अनुसार देश में अब तक केंद्र ने 1.92 लाख टन चना दाल एवं तूर दाल की खरीदी एवं 1.83 लाख टन सरसों के बीज की खरीदी (कुल मिलाकर 3.75 लाख टन) मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कर ली है।

कोरोना वायरस की महामारी से एक बात ज़रूर सीखी गई है कि अब विश्व के लगभग सभी देश यह महसूस करने लगे हैं कि देश में आंतरिक सप्लाई चेन का बहुत मज़बूत होना ज़रूरी है। आवश्यक राशन सामग्री एवं दवाईयों का उत्पादन तथा इनका पर्याप्त भंडारण देश में ही होना चाहिए। ऐसे समय में विदेशों से आयातित सामग्री पर लम्बे समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता।

पूरे विश्व में फैली कोरोना वायरस की महामारी अपने आप में अभूतपूर्व संकट है जो पूर्व में कभी भी नहीं देखा गया है। विश्व व्यापार संगठन के एक आकलन के अनुसार वैश्विक विदेशी व्यापार, उक्त कारणों के चलते, लगभग 32 प्रतिशत तक गिर सकता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है कि इस महामारी के चलते पूरे विश्व में लगभग 9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि से कुल आय कम होने की सम्भावना है। जिसके कारण एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पुनः ग़रीबी रेखा के नीचे आ जाएँगे। ऐसी विकट स्थिति में सप्लाई चेन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भारत ने अपने देश में सप्लाई चेन को मज़बूत रखने में बहुत बड़ी सफलता पाई है।

(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट से निपटने को देश सेवा में जुटी भाजपा

► शिवप्रकाश

को विड -19 से सम्पूर्ण विश्व इस समय प्रभावित है। इस वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में होने के कारण चीन घृणा का पात्र भी बना है। वायरस के कारण विश्व भर में लगभग 25 लाख 42 हजार लोग प्रभावित हैं। 176404 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत में भी लगभग 20 हजार लोग कोरोना की चपेट में हैं। 623 लोग आज तक काल के गाल में भारत में भी समा चुके हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा संकट मंडरा रहा है।

भारत में कोरोना संक्रमण के खतरे को मोदी सरकार ने बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था। विदेश से वायु सेवा के द्वारा भारत में आने वाले लोगों की विमानपत्तन पर जांच भी प्रारंभ हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। एक दिन का जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन का प्रभावी क्रियान्वयन कारगर साधन सिद्ध हुए है। इन प्रभावी उपायों के कारण विश्व की अलग-अलग एजेंसियों ने कोरोनावायरस की रोकथाम में विश्व के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम स्थान दिया है।

भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी है। जो राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या में विश्व में सबसे बड़ी है। भाजपा का सिद्धांत है Nation First (राष्ट्र प्रथम)। जनसंघ काल से वर्तमान भारतीय जनता

पार्टी तक जब-जब भी देश के सम्मुख कोई प्रश्न आया, उसके समाधान के लिए भाजपा नेतृत्व सदैव सक्रिय रहा है। ऐसे समय में भाजपा के असंख्य कार्यकर्ता अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। गत 70 वर्षों के इतिहास में अनेक प्रसंग इसका स्मरण कराते हैं।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण हमारे देश में गरीबों के सम्मुख रोजी-रोटी का प्रश्न आया इसका अनुमान भाजपा नेतृत्व को था। रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाने वाले मजदूरों के सम्मुख भी समस्या खड़ी होगी। वृद्धजनों के सम्मुख नियमित दवाइयों का भी एक प्रश्न आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस संकट की घड़ी में देशभर के असंख्य कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उनके विडियो कॉन्फ्रेंस (संवाद) के द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से संवाद का क्रम प्रारंभ हुआ।

देश भर के समस्त जिला अध्यक्षों तक इस संवाद का क्रम चला जो अलग-अलग श्रेणी के अनुसार अभी तक जारी है। लाखों कार्यकर्ताओं तक पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी स्वयं एवं अपने पदाधिकारियों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा चुके हैं। देश के अन्य दल चुनाव लड़ने तक ही अपनी भूमिका मानते हैं, वे इस अवसर पर कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ दल सरकारी राशन पर अपने नेता की फोटो एवं चुनाव चिन्ह छपवाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान

रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बूथ तक विस्तृत सेवा का कार्य किया है।

#FeedtheNeedy के अंतर्गत पार्टी ने लगभग 10 करोड़ भोजन पैकेट एवं 2 करोड़ 21 लाख कच्चे राशन की मोदी किट बनाकर गरीब परिवारों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। वायरस से मुक्ति मिलने के बाद भी हमको फेस कवर का उपयोग लंबे समय तक करना होगा। इसलिए महिला मोर्चा की असंख्य महिलाओं ने घर-घर फेस कवर बनाने का कार्य किया। अब तक लगभग 2 करोड़ 25 लाख फेसकवर देश के नागरिकों तक पहुंच चुके हैं।

विश्व भर में आरोग्य सेतु एप दुनिया का सबसे तेज गति से डाउनलोड होने वाला एप बन गया है। जिसको डाउनलोड कराने में भाजपा कार्यकर्ता सहायक बने हैं। लाखों बूथ के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद देकर कोरोना संक्रमण के समय बचाव में लगे लोगों का मनोबल बढ़ाया। #PMCAresFund में लगभग 30 लाख से भी अधिक लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। यह कार्य देश के समस्त राज्यों के सभी जनपदों में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है।

पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसमें केवल अपनी व्यक्तिगत छवि को सुधारने की जिद ही ज्यादा दिखाई देती है। लॉकडाउन के पालन में शिथिलता, समस्त जमातियों की जांच ना होना, कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों के संबंध में भी अलग-अलग बयानबाजी ने बंगाल की जनता में संदेह उत्पन्न किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी सुरक्षा के संबंध में संदेह है। राशन के वितरण में भी पक्षपात के कारण

बंगाल की गरीब जनता परेशान है।

इस विषम परिस्थिति में भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने राहत एवं सेवा कार्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। बंगाल के बाहर अलग-अलग राज्यों में पश्चिम बंगाल के लाखों नागरिकों को उन-उन राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है। बंगाल के सभी जिलों में राहत कार्य अभी भी अनवरत चल रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में एक लाख से अधिक भाजपा कार्यकर्ता कोलकाता में कंट्रोल रूम बनाकर निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में सक्रिय हैं। अब तक लगभग 17 लाख 45 हजार भोजन पैकेट एवं 22 लाख लोगों के लिए कच्चे राशन की व्यवस्था बंगाल भाजपा ने की है। 77 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन औसत भोजन भाजपा कार्यकर्ता देते हैं। 93 हजार लोगों के द्वारा PMCAresFund में सहयोग भी हुआ है। 6 लाख 66 हजार फेस कवर महिलाओं द्वारा बनाये एवं वितरित किये गये हैं।

“नर सेवा, नारायण सेवा” का संकल्प लेकर चलने वाला यह कार्य उत्कृष्टतम सेवा का उदाहरण है। देश के लगभग 1500 राजनीतिक दलों में यह भाजपा को शेष से अलग (Party with a difference) करता है। जहाँ शेष दल केवल सत्ता के माध्यम से अपनी एवं अपने परिवार की स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं, वहीं भाजपा दीन, दुखी, पीड़ित एवं गरीबों की सेवा कर रही है। हम सभी भाजपा के बने एवं भाजपा हमारी बने यही भविष्य की दिशा होनी चाहिए।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं।)

संकट की इस घड़ी में हर तरह से देश के नागरिकों के साथ खड़ी है मोदी सरकार

► नवोदित सक्तावत

को रोग वायरस के बढ़ते प्रकोप से आम जनता को बचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। राजधानी दिल्ली एवं इससे सटे नोएडा में गत दो-तीन दिनों से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन जारी था। इनमें से अधिकांश लोग किसी अफवाह के चलते बाहर निकल आए थे। अधिकांश का कहना था कि उनके मकान मालिक उनके किराये को लेकर परेशान कर रहे हैं एवं कई के पास अब खाने की समस्या भी है, इसके चलते वे सड़कों पर उतर आए हैं।

शनिवार रात इसी प्रकार की अराजकता दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर देखने को मिली जहां हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन हालातों पर नियंत्रण के लिए तुरंत निर्णय लिया है। सरकार ने मजदूरों के लिए रहने व खाने का इंतजाम किया है जो लोग अपने गृहनगर के लिए लंबी दूरी पर पैदल ही चल निकले थे उनके लिए बस आदि से परिवहन का भी इंतजाम किया गया।

सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से गंभीर है कि लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि श्रमिक वर्गों की परेशानी को लेकर उन्हें अफसोस है, साथ ही देश की जनता घरों में कैद हो गई है, उसे लेकर भी पीड़ा है लेकिन देश भर के हित को देखते हुए इस प्रकार का कड़ा निर्णय लेना ही पड़ा।

प्रधानमंत्री ने हर आम व खास से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया है। कोरोना वायरस पूरे विश्वी पर कहर बनकर टूटा है। दुनिया के कई देशों सहित भारत में संक्रमितों एवं मृतकों की संख्यां रोज बढ़ती जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार ने शुरुआती तौर पर देश के कई शहरों में लॉकडाउन घोषित किया। हालात और बिगड़ते गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम फैसला लेते हुए समूचे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। लेकिन लॉकडाउन से जनजीवन के बुरी तरह प्रभावित होने का अंदेशा सरकार को था, इसके चलते अब सरकार ने समाज के गरीब वर्ग की सुध लेते हुए उनके लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का सहारा मिलने के बाद अब निर्धन वर्ग इस 21 दिनी लॉकडाउन की अवधि में गुजर बसर कर सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के समक्ष 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद ही सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की थी।

सरकार को अपने नागरिकों, कर्मचारियों, स्वा स्व्या अमले और श्रमिक वर्ग सभी की चिंता है, इसके चलते इस आपात घड़ी में महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमितों को बचाने के लिए काम कर रहे स्वा स्व्या कर्मचारियों के लिए भी 50 लाख रुपए के मेडिकल

इंश्योरेंस किए जाने की घोषणा की गई है।

राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 21 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के लिए यह अच्छीभ तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कोई भी नागरिक भूखा न रहे।

तय व्यवस्था के अनुसार अब हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल अगले तीन महीने तक अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के हिसाब से 1 किलो दाल भी दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि डॉक्टर्सों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। किसानों को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्तीमंत्री ने कहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खातों में 2 हजार की किश्त डाल दी जाएगी। देश भर के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाएगा। इससे देश के पांच करोड़ परिवार को व्यवस्थाल का लाभ मिलेगा। तकरीबन हर मजदूर को 2 हजार रुपए ज्यादा का लाभ मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना का असर कुछ लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन भले ही तीन सप्ताह का किया हो लेकिन राहत का विचार आगामी 3 महीनों का ध्यान में रखकर किया गया है और उसके अनुसार ही घोषणाएं की गई हैं।

इसी क्रम में गरीब, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग लोगों को एक बार 1 हजार रुपए दिए जाएंगे, यह राशि उन्हें तीन महीने में उन्हें दी जाएगी। इसका लाभ देश भर के 3 करोड़ गरीब बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा। देश की

ऐसी 20 करोड़ महिलाएं जिन्होंने जन धन खाता खोला है उनके इस खाते में आगामी तीन महीने तक 500-500 रुपए की राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम का लाभ लेने वाली महिलाओं को अगले तीन महीने तक उन्हें 3 घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

इसका लाभ 8.2 करोड़ बीपीएल परिवार को सीधे तौर पर मिलेगा। कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि संगठित क्षेत्र और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए अगले तीन महीने तक भविष्य निधि का हिस्सा भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। 24 फीसदी हिस्सा भविष्य निधि के खाते में भारत सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। यह व्यवस्थाल उन संस्थागनों के लिए लागू होगी, जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और वहां 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपए से कम है।

इसके अलावा, ईपीएफओ योजना के तहत सरकार नियमों में संशोधन भी करने जा रही है ताकि कर्मचारी अपने नॉन रिफंडेबल फंड में से 75 फीसदी या फिर तीन महीने का वेतन दोनों में से जो भी कम हो उतनी राशि का आहरण सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संकट के इस दौर में मोदी सरकार देश के हर नागरिक के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी है और कोरोना से बचाने के लिए तत्पर है। उम्मीद है देश जल्दक ही इस मुसीबत से मुक्ता होगा और जनजीवन, अर्थव्यवस्थाद दोबारा पटरी पर होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना महामारी से भारत की लड़ाई दुनिया के लिए विस्मय और प्रेरणा का विषय बन चुकी है

► प्रणय कुमार

भारत अपनी विशाल-सघन जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों के मध्य भी जिस दृढ़ता, साहस एवं संकल्प के साथ कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वह पूरी दुनिया के लिए विस्मय, औत्सुक्य एवं गहन शोध का विषय है। अपितु उत्सुकता एवं शोध से अधिक आज यह यूरोप और अमेरिका के लिए अनुकरण और प्रेरणा का विषय बन चुका है।

भले ही नस्लीय दर्प एवं श्रेष्ठता-दंभ में पश्चिम का प्रशस्ति-गायन करने वाली पत्र-पत्रिकाएँ आज भी भारत को उन्हीं पुरानी स्थापनाओं और पूर्वाग्रहों से आकलित करें, पर उन्हें भी यह सच दिख रहा है कि कैसे अब भी भारत ने इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या हजारों में और मृतकों की संख्या सैकड़ों में समेट रखी है! उन्हें यह सच पच नहीं रहा, इसलिए वे इस अवसर की ताक में आज भी खड़ी दिखाई देती हैं कि वे वही पुराना राग अलापें कि देखा हमने कहा था न कि प्रगति के तमाम आधुनिक एवं वैज्ञानिक दावों के बीच आज भी भारत अपने मूल चरित्र में वही पुराना, अल्प विकसित, पिछड़ा एवं लाचार देश है।

बीबीसी आदि वामपंथी मानसिकता से ग्रस्त मीडिया संस्थानों में इसी निहितार्थ से समाचार दिखाए व परोसे भी जा रहे हैं। पर ज़मीनी सच्चाई बिलकुल अलग है।

इस महामारी से निपटने में पश्चिमी समाज और वहाँ का जागरूक नेतृत्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। पश्चिमी ही क्यों, दुनिया के सभी मानव-प्रेमियों के लिए भारत का यह दृष्टिकोण मायने रखता है कि आर्थिक समृद्धि से अधिक महत्त्व मानव संसाधनों का है।

राज्य का पहला कर्तव्य अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा है, न कि अर्थव्यवस्था की चिंता। अर्थव्यवस्था का क्या है, यदि जीवन बचा तो इसे पुनः पटरी पर ले आया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व-नेता के रूप में संपूर्ण जगत में स्थापित किया है। इस एक दृष्टिकोण ने भारत की सदियों से चली आ रही उच्च एवं उदार मानवीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करा दी।

एक ओर जहाँ अमेरिका और इंग्लैंड जैसे अति विकसित देश इस भयावह आपदा-काल में भी आर्थिक हितों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए देर से चेते, वहीं भारत का यह मानवीय दृष्टिकोण पूरी दुनिया के लिए एक बेजोड़ मिसाल बन गया है। बात केवल नीति और नीयत के स्तर पर ही प्रशंसनीय नहीं रही, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तमाम राज्य सरकारों ने पूरी चुस्ती एवं स्फूर्ति दिखलाई।

लंदन में कार्यरत भारतीय डॉक्टर राजीव मिश्रा बताते

हैं कि वे और उनका पूरा परिवार विगत 18 दिनों से कोरोना की चपेट में था। हाल ही में उससे उबरने के पश्चात उनका कहना है कि इंग्लैंड की सरकार ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वहाँ की सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि ऐसी भयावह आपदा में वह लाचार है, बेबस है, चुपचाप मरीजों को इस बीमारी से लड़ता-मरता देखने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। कोई अपनी मज़बूत प्रतिरोधात्मक क्षमता के बल पर इस संक्रमण से उबर पाए तो यह उसका भाग्य!

वे आगे कहते हैं कि भारत ने जिस समय से एयरपोर्ट पर यात्रियों की जाँच करना, कोरोटाइन करना, उन्हें आइसोलेशन आदि में रखना शुरू कर दिया उस समय तो यूरोप और अमेरिका में जाँच आदि के नाम पर प्रारंभिक औपचारिकताएँ भी नहीं प्रारंभ की गई थीं। सरकारें तो छोड़िए आकंठ भोग में डूबी कथित अनुशासित पश्चिमी सभ्यता को भी त्याग, संयम और अनुशासन की दिनचर्या अपनाने में लंबा वक्त लगा, जबकि भारत का बहुसंख्य समाज इसे अपनी सहज जीवन-शैली की तरह आत्मसात कर पाया।

भारत सरकार ने लॉकडाऊन की घोषणा भी सर्वथा उपयुक्त समय पर की। यदि चंद अवसरवादी राजनीतिक कुचक्रियों, जहरीली जमातों, सिरफ़िरे जत्थों ने जाने-अनजाने इसका उल्लंघन न किया होता तो अब तक इस महामारी पर लगभग पूरी तरह से अंकुश एवं नियंत्रण पा लिया गया होता। राजीव मिश्रा का कहना है कि कुछ लोग भारत में व्यर्थ ही टेस्टिंग का मुद्दा उछाल ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। गौरतलब है कि वे स्वयं डॉक्टर हैं और वे कहते हैं कि क्या गारंटी है कि टेस्टिंग के बाद इस महामारी से कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा?

सवाल है कि भारत जैसे सीमित चिकित्सकीय संसाधनों एवं विशाल जनसंख्या वाले देश में सरकार पहले

संक्रमित लक्षणों वाले मरीजों का परीक्षण करे या एक-एक की टेस्टिंग करे? फिर भी सरकार ने अल्पावधि में कोरोना के परीक्षण के लिए टेस्टिंग लैब्स स्थापित किए, किट्स तैयार किए, पाँच सौ से लेकर हजार बेड्स वाले वैकल्पिक हॉस्पिटल्स तैयार किए। एक सरकार भला इतने कम समय में और क्या-क्या कर सकती है?

यह एक ऐसी महामारी है कि कोई भी सरकार अकेले दम पर इससे नहीं निपट सकती। अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड जैसे अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले विकसित देशों की सरकारों ने भी इस महामारी के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत सरकार इस महामारी से निपटने के लिए अभी भी हर संभव प्रयास कर रही है, दिन-रात और लगातार कर रही है। आवश्यकता समाज के रूप में उसके प्रयासों को सफल बनाने की है। अपनी नागरिक जिम्मेदारियों के निर्वाह की है।

पुलिस-प्रशासन, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड एवं सफाई योद्धाओं आदि ने इस संकट-काल में नर-सेवा, नारायण-सेवा का देव-दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका प्रयास न केवल सराहनीय अपितु स्तुत्य है। उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि हतोत्साहित करने की। विभिन्न शहरों में उन पर होने वाले सुनियोजित हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

जमातियों के कुकृत्यों की जितनी निंदा की जाय, उतनी कम है। यदि आज उन्हें संक्रामक मानवबम की संज्ञा दी जा रही है तो किसी को क्यों कर आपत्ति होनी चाहिए? इन जमातियों की कारगुजारियों का अनुमान इसी आँकड़े से लगाइए कि तमिलनाडु में 89 प्रतिशत, तेलंगाना में 78 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 70 प्रतिशत, असम में 90 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 58 प्रतिशत, दिल्ली में 65 प्रतिशत संक्रमित मरीज जमाती हैं।

पुलिस-प्रशासन तो इतनी बड़ी संख्या में जमातियों

द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना फैलाए जाने के पीछे के षड्यंत्रों की सघन जाँच और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर ही रही है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि समाज के हर तबक्रे से ऐसे कार्यों की निंदा और भर्त्सना के चतुर्दिक स्वरो की गूँज सुनाई देनी चाहिए, केवल सलमान खान जैसे इक्का-दुक्का स्वर नहीं, बल्कि मजहब की संकीर्णताओं और संकुचितताओं से ऊपर उठकर तमाम मौलवियों, इमामों, सेकुलरिज्म के झंडेबरदारों को समवेत स्वर में इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। अन्यथा समाज में विभाजन की ऐसी रेखा खिंच जाएगी जिसे पाटना कठिन होगा।

तमाम राजनीतिक दलों को भी निहित स्वार्थों एवं वोट-बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में ऐसे कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। उनसे अपील करनी चाहिए कि महामारी हिंदू या मुसलमान नहीं देखती? क्या अच्छा नहीं होता कि राहुल गाँधी अपने हालिया एक घण्टे के वक्तव्य में तबलीगियों के इन कुकृत्यों पर भी दो शब्द

बोलते? इंदौर, कानपुर, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आदि में तबलीगियों एवं वर्ग विशेष द्वारा किए गए हमले और हंगामे की आलोचना करते?

भारतीय राजनीति कब परिपक्व होगी? कब वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर एक साथ खड़ी दिखेगी? क्या मोदी विरोध के अंधत्व में हर अनुचित को उचित ठहराया जाना उपयुक्त एवं कल्याणकारी है?

यह समय सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक मतभेदों, पूर्वाग्रहों, धारणाओं को भुलाकर साथ आने का है। अभी प्रत्येक भारतवासी का एक ही लक्ष्य और एक ही धर्म होना चाहिए, वह यह कि कोरोना के संक्रमण का वाहक बनने से स्वयं बचना और दूसरों को भी बचाना। एक बार इससे उबर जाने के पश्चात हम संपूर्ण राष्ट्र के सामूहिक संकल्प एवं सहयोग के बल पर भूख, गरीबी अभाव आदि पर भी निश्चित विजय प्राप्त करेंगे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

दवा उद्योग के क्षेत्र में विकसित देश भी अब भारत पर निर्भर

▶ प्रह्लाद सबनानी

विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता का अभी हाल ही में आभार प्रकट किया है क्योंकि भारत ने अमेरिका को कोरोना वायरस को नियन्त्रित करने हेतु हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई है। यह दवा ब्राजील एवं श्रीलंका के साथ ही विश्व के कई अन्य देशों को भी उपलब्ध कराये जाने पर इन देशों के राष्ट्रपतियों ने भी भारत का आभार जताया है।

दवा क्षेत्र में भारत आज विश्व में कई विकसित देशों से भी बहुत आगे निकल आया है। यह सब अचानक नहीं हुआ है। भारत को, दवा क्षेत्र में, विश्व में प्रथम पंक्ति में ला खड़ा करने के पीछे केन्द्र सरकार की कई योजनाओं की मुख्य भूमिका रही है। आप यह जानते ही हैं कि स्वास्थ्य, दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वोपरि महत्व का क्षेत्र है। यही वजह है कि दवा उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में भी देखा जाता है। भारतीय दवा उद्योग वैश्विक फार्मा सेक्टर में एक उल्लेखनीय स्थान हासिल कर चुका है और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है।

भारतीय दवाओं का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है भारतीय दवाओं की गुणवत्ता एवं भारतीय कम्पनियों की साखा। भारतीय कम्पनियों ने

विदेशी दवा बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। आकार के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा बाजार है। वहीं कीमत के लिहाज से भारत दुनिया का 13वां सबसे बड़ा दवा बाजार है। दुनिया में बीमारीयों के टीकों की 50 प्रतिशत मांग भारतीय दवाईयों से पूरी होती है। अमेरिका में दवाओं की 40 प्रतिशत पूर्ति भारतीय दवाओं से होती है। वहीं ब्रिटेन में कुल दवाओं की 25 प्रतिशत पूर्ति भारतीय दवाओं से होती है। आज भारतीय फार्मा उद्योग का कुल आकार लगभग 40 अरब अमेरिकी डालर का हो गया है।

2015-2020 के बीच भारतीय दवा उद्योग के 22.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की गई है। भारत से 200 देशों को दवायें निर्यात की जा रही हैं। भारत से वर्ष 2017-18 में 17.27 अरब अमेरिकी डालर के मूल्य की दवाओं का निर्यात किया गया था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 19.14 अरब अमेरिकी डालर एवं वर्ष 2019-20 में 22 अरब अमेरिकी डालर हो जाने की सम्भावना है।

वर्ष 2017 में USFDA ने भारतीय कम्पनियों के 304 नये दवा आवेदनों को मंजूरी दी थी। इससे अमेरिकी जेनेरिक दवाओं के 70-80 अरब अमेरिकी डालर के बाजार में भारतीय जेनेरिक दवाओं की मौजूदगी 30 प्रतिशत और भारतीय दवाओं का मुनाफ़ा 10 प्रतिशत

बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा बायो मेडिसिन, बायो सर्विस, जैव कृषि, जैव उद्योग और बायो इन्फोर्मेशन के क्षेत्र के कुल मिलाकर 30 प्रतिशत विकास के साथ वर्ष 2025 तक 100 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।

भारतीय कम्पनियों को विदेशों में यदि जेनेरिक दवाओं के निर्यात की इजाजत नहीं मिलती है तो वे वहां की स्थानीय कम्पनियों को खरीद लेती हैं और अपनी पैठ इन देशों में बना लेती हैं। क्योंकि जेनेरिक ब्रांडेड दवाएं तुलनात्मक रूप से बहुत सस्ती होती हैं। भारतीय दवा उद्योग के विकास में केन्द्र सरकार की नीतियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी दवा कम्पनियों के अधिग्रहण सम्बंधी नियमों को आसान बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप, भारतीय दवा उद्योग ने 2017 में 1.47 अरब अमेरिकी डालर मूल्य की 46 छोटी बड़ी विदेशी दवा कम्पनियों का अधिग्रहण एवं विलय किया था। इससे अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों में भारतीय दवा उद्योग का निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है।

उम्मीद है, भारतीय दवा उद्योग साल 2020 तक विश्व के शीर्ष तीन दवा बाजारों में और मूल्य के लिहाज से 6वां सबसे बड़ा आकार वाला देश होगा। केन्द्र सरकार के फार्मा विजन 2020 का मकसद भारत के दवा उद्योग को विश्व में मुख्य स्थान दिलाना है। फार्मा विजन को प्रभावी बनाने के लिये अनुसंधान एवं इनोवेशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन फ़ील्ड फ़ार्मा परियोजनाओं के लिये आटोमेटिक रूट के अन्तर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा चुकी है जब कि ब्राउन फ़ील्ड फ़ार्मा परियोजनाओं में आटोमेटिक रूट के तहत 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अधिक की राशि

के लिये सरकारी अनुमति की आवश्यकता रखी गई है।

भारत जेनेरिक दवाओं के मामले में विश्व में काफ़ी आगे है। दरअसल जेनेरिक दवाओं की ब्रांडेड संरचना ब्रांडेड दवाओं के अनुसार ही होती है। लेकिन वो रासायनिक नामों से ही बेची जाती है ताकि जनता को कोई उलझन न रहे। क्रोसिन और कालपोल, ब्रांडेड दवाओं के वर्ग में आती हैं, जबकि जेनेरिक दवाओं में इनका नाम पैरासिटामाल है। जेनेरिक दवाओं और दूसरी दवाओं में क्या अन्तर है? आईये, इसे समझने का प्रयास करते हैं।

जब कोई कम्पनी कई सालों की रिसर्च के बाद किसी दवा की खोज करती है तो उस कम्पनी को उस दवा के लिये पेटेंट मिलता है जिसकी अवधि 10 से 15 वर्ष की रहती है।

पेटेंट अवधि के दौरान केवल वही कम्पनी इस दवा का निर्माण कर बेच सकती है, जिसने इस दवा की खोज की है। जब दवा के पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तब उस दवा को जेनेरिक दवा कहा जाता है। यानि, पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद कई अन्य कम्पनियां उस दवा का निर्माण कर सकती हैं। परन्तु इस दवा का नाम और कीमत अलग-अलग रहता है। ऐसी स्थिति में दवा जेनेरिक दवा मानी जाती है। भारतीय बाजार में केवल 9 प्रतिशत दवाएं ही पेटेंटेड श्रेणी की है और 70 प्रतिशत से अधिक दवाएं जेनेरिक श्रेणी की हैं।

जेनेरिक दवाएं सबसे पहले भारतीय कम्पनियां ही बनाती हैं। अमेरिका एवं यूरोपीयन बाजार को सबसे सस्ती जेनेरिक दवाएं भारतीय कम्पनियां ही उपलब्ध कराती हैं। चीन के मुकाबले भारतीय जेनेरिक दवाएं ज्यादा गुणवत्ता वाली मानी जाती हैं और कीमत में भी सस्ती होती हैं। पूरे विश्व में विदेशों को कुल निर्यात हो रही दवाओं में भारत का हिस्सा 20 प्रतिशत है।

जेनेरिक दवाएं ब्रान्डेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं, इसीलिये केन्द्र सरकार ने जेनेरिक दवाओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु भारत में जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों पर 600 से ज्यादा जेनेरिक दवाईयां सस्ते दामों पर मिलती हैं एवं 150 से ज्यादा सर्जिकल सामान भी सस्ती दरों पर उपलब्ध है।

दुनिया भर में भारतीय जेनेरिक दवाओं पर विश्वास बढ़ा है और ये देश अब भारत से ज्यादा से ज्यादा आयात करने लगे हैं। अमेरिकी बाज़ार के जेनेरिक दवाओं में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यूएसएफ़डीए के

अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुनिया भर के 323 दवाईयों की टेस्टिंग की गई थी। इस टेस्टिंग में भारत की सभी दवाएं पास हुई थीं।

इसके साथ ही, भारत में उत्पादन इकाईयों के मानकों को सही ठहराते हुए अमेरिकी एफ़डीए ने भारत की ज्यादातर उत्पादक इकाईयों को अमेरिका में निर्यात की अनुमति दे दी है। जाहिर है, जेनेरिक दवाइयों के बाज़ार में भारतीय कम्पनियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

Stealing Grains – PDS Scam and TMC’s Politics of Pandemics in West Bengal

► Dr. Anirban Ganguly

News crept in... that villagers were getting mobilised against corruption in the public distribution system (PDS). They marched to the local ration dealer’s house, demanded compensation, negotiated fines; in some places people turned violent, assaulted dealers, ransacked their property or torched their houses. In some cases the police retaliated, fired at the crowd causing injuries, even death...” The opposition Trinamool Congress, identified this as a “popular upsurge” against “the anti-peoples’ policy” of the Left Front government. This was 2006 in Bankura, where the anti-PDS scam drive was particularly forceful. Turn this story to April-May 2020, the roles have reversed. The ruling Trinamool Congress’s local leaders, ministers, elected municipal leaders have been caught pilfering ration provisions and bearing the brunt of the people’s disgust for siphoning these.

The Left parties in West Bengal initially made a semblance of protest but

are naturally lukewarm in their drive to expose the TMC. They believe that exposing the TMC will only strengthen the BJP’s contention that the ruling TMC’s leaders were involved in scooping off grains meant for distribution to the NFSA card holders for the next three months as a special allocation by the Narendra Modi government.

As on the month of May 2020, districts across West Bengal are seeing people protest in large number against the irregularities in PDS distribution. Local leaders of the Trinamool Congress, elected Panchayat and local body members are being accosted by people who are exasperated at the fact that the ruling party in the state, even in a time of pandemic, is ensuring that rice and grains meant for the poor are pilfered for and by party apparatchiks.

One of the first things that Prime Minister Modi announced was the PM GaribKalyan Anna Yojana (PMGKAY) (grains) and (pulses). His mantra for the

lockdown period was that the ordinary people, those dependent on the PDS system should not suffer at all and that their stocks of grains and pulses must be replenished. No one should go hungry. In line with that pledge the PMGKAY was initiated: 80 crores beneficiaries were targeted – they were to be given 5Kg grains for free for the next three months, an amount of Rs.46,061 crore was allotted, to be precise, lifting commenced and distribution started with the target of concluding the exercise by the end of April.

As part of the second portion of this huge exercise, under the PM-GKAY (pulses) 19.4 crore households were targeted as beneficiaries for receiving 1 kg free pulses for three months, an amount of Rs.5000 crore was earmarked and by 25 April, the Modi government had fulfilled its commitment to lift these in the respective state FCI storage facilities. As per the system, the respective state governments and union territories were to submit a lifting plan and would then have to lift and distribute their share of the ration allotted by the Union government.

PM Modi has always talked about team India, about cooperative federalism and even now, during the pandemic

challenge he has worked according to that fundamental belief and faith. By and large the Indian states and their leaders and ruling dispensation have also displayed the spirit of cooperative federalism, the only exception being, the Mamata Banerjee led TMC government in West Bengal.

Among the many irregularities that the Mamata Banerjee government is committing in its bid to tackle the Corona pandemic, is one which especially displays its desperation and crassness. Since the last few weeks, to be precise from the first week of April 2020, reports started pouring in from across the state of irregularities in the distribution of PDS. Those who were on the ground, noticed that the Trinamool leaders at the local level were actively pilfering ration provision meant for distribution through the PDS system. These were then distributed as relief from the party with the TMC supremo's stickers and photos pasted on them. While this happened, Mamata Banerjee and her food minister made a public display of being discriminated against by the Modi government, saying that the Union government was not releasing the state's quota of food grains. In the days to come this proved to be a patent lie. This

ruse was resorted to in order to create confusion and divert attention from the fact that the TMC's leaders were involved in stealing provisions which was actually meant for ration card holders, while also ensuring that Mamata could complain and tell the over 6 crore NFSA (National Food Security Act) card holders in the state that the Modi government had not fulfilled its promise of providing them with provisions in these difficult times. The Chief Minister needlessly went into trying to score political points. Her attitude, since the beginning of the pandemic has been negative. Initially she had publicly observed that Corona was a balloon floated by Modi to divert attention from the Delhi riots. She is the only elected Chief Minister of a State to make such a comment publicly.

The TMC's duplicity on the PDS scheme was called out by Governor of West Bengal Jagdeep Dhankar, who in his letter to the Chief Minister dated 20.4.2020, pointed out that Union Food Minister Ramvilas Paswan had clearly stated that though the FCI was in complete readiness there was complete inaction on the part of the state government.

In between this expose, and in face of increasing protests against her party-men

across the state for stealing provisions from PDS stores, Mamata Banerjee, dismissed her food secretary, Manoj Aggarwal, sending him on compulsory waiting. Except for some perfunctory admonitions, she refused to take action against any of her party workers and leaders. The TMC government had tripped and most saw this action against the food secretary as an unnecessary vendetta against the bureaucrat with the party leaders being lightly let off. Even this change failed to stem the tide of protests.

The Governor's letter was followed by another letter from the Joint Secretary of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution to the new secretary of the food department of West Bengal. The letter exposed the lie, by clearly spelling out the allocation made under the PMGKAY and the dereliction in this regard by the Mamata Banerjee government. The ministry's letter dated 23rd April 2020, (D.O. No.1-2/2020-PD-II) pointed out that the government of India "in association will all States/UTs has "started the distribution of additional free food grains @ 5Kg per person to all NFSA ration card holders for a period of 3 months (April to June 2020), to ensure

the food security of all 80 crore poor and needy beneficiaries covered under the NFSA, so that they do not suffer on account of non-availability of food grains during the ongoing period of crisis.”

The letter next pointed out that though the allocation of food grains and the system to be followed was conveyed to all states and union territories on 30th March 2020, itself, and though most states have “have already started lifting and distribution of these additional food grains to the NFSA beneficiaries besides distribution of regular NFSA entitlements”, in the case of the West Bengal government alone, “it is observed that no action has been initiated so far for the distribution of additional food grains (Rice) to NFSA beneficiaries under this special time bound scheme.” S. Jagannathan, joint secretary in the ministry of consumer affairs and public distribution system, ended his letter with the following appeal to the state government, “a month-wise distribution of free food grains under PM-GKAY scheme may be started for all 6.02 crore beneficiaries covered under NFSA without losing any further time. An immediate action would be in the interests of the beneficiaries during this time of crisis.”

This punctured the Mamata Banerjee

government’s false claims and exposed the deliberate and intentional delay on her part. The politics of pandemic was being played out at the cost of 6.02 crore hungry and needy people. Irregularities in ration card distribution, local party henchmen taking their cut of grains from the poor, local party bosses hoarding provision to distribute in “Didi’s” name, all these continue to be part of the PDS Scam saga. Meanwhile, Mamata Banerjee continued to remain silent, leading people – especially in the hinterlands – to conclude that she is complicit in this system of siphoning off.

Through these news and reports of continuing pilferage, what is heartening is that people have begun to protest. The people of West Bengal seem to have seen through the “Maa-Maati-Maanush” slogan, a hollow and exploitative slogan. Videos have surfaced of how ordinary people caught red handed rice bags being pilfered into a rice mill for hoarding and distribution, of angry mob setting on fire ration shops, as of writing this, reports are coming in from across the state, in Bhangar, in South 24 parganas, for instance, of large number of ration cards being recovered from the house of a TMC panchayat pradhan, clashes

between two TMC factions on this count, protests by people against ration theft from Nandigram, Lalgola, Salar, Domkal, Sagardighi – all situated in various districts across the state are pouring in on a daily basis.

Having unseated the Left front regime, Mamata Banerjee has now outdone the Left in its exploitative politics. It is a politics in which lumpen-cartels of cut-money dealers abound, a politics which, while paying lip service to the poor and the marginalised, actually props itself up and survives on suppressing their

aspirations and snatching away their legitimate dues. The PDS scam not only exposes the most insensitive dimension of Mamata Banerjee's brand of politics but it also one of the worst manifestations of the politics of pandemic.

The one redeeming factor is that the victims of that politics have now begun standing up. A clear back-clash is visible and a wave of discontent is brewing across West Bengal.

(The writer is Director, Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, New Delhi, views expressed are his own)

विपक्ष कुछ भी दलील दे, कोविड के खिलाफ लड़ाई में आंकड़े मोदी सरकार की सफलता की ओर ही इशारा करते हैं

► शिवानंद द्विवेदी

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसे लॉकडाउन 3.0 कहा जा रहा है। पहले के दो चरणों के लॉकडाउन की तुलना में तीसरा चरण कुछ मामलों में अलग है। तीसरे चरण में जिलों के रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर कुछ क्षेत्रों को सशर्त छूट दी गयी है। मसलन ग्रीन जोन जिलों को यातायात, बाजार सहित कुछ सेवाओं के लिए तय निर्देशों के तहत शुरू करने की अनुमति मिली है। वहीं येलो जोन में भी कुछ छूट मिली है।

फिलहाल देश के 733 जिलों में से 130 जिले रेड जोन, 284 जिले येलो जोन तथा 319 ग्रीन जोन में हैं। हालांकि रेल व हवाई यात्रा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि को लेकर किसी भी जोन में किसी प्रकार की कोई छूट 17 मई तक के लिए नहीं है। लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में देश के 17 फीसद जिलों में रेड जोन की पाबंदियां बरकरा रहेंगी। वहीं 38 फीसद जिले येलो जोन को मिले छूट वाले होंगे। देश के 43 फीसद ग्रीन जोन जिलों में स्थानीय यातायात, सरकारी कामकाज, चयनित दुकानों तथा श्रम व मजदूरी से जुड़े कार्यों को सशर्त छूट मिली है। कहने का आशय यह है कि देश के बड़े हिस्से के लिए शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट देने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। हालांकि इसमें राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

लॉकडाउन 3.0 से यह शुरूआती संकेत मिलते हैं कि सरकार ने 'संपूर्ण देशबंदी' जैसी स्थिति से निकलने की कारगर राह तलाशनी शुरू कर दी है। साथ ही सरकार की नजर उन जगहों पर भी केंद्रित है, जहां कोरोनावायरस का खतरा अधिक संभावित है। निस्संदेह गत डेढ़ महीने में मोदी सरकार के निर्णयों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी सफलता हासिल हुई है। लॉकडाउन का निर्णय सही साबित होता दिख रहा है।

चूंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है। कई मामलों में इसे वर्षों तक मानव जीवन को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। ऐसे में विश्लेषण के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय दो कारणों से असर कारक कहा जा सकता है। पहला यह कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन करके 'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' की स्थिति से देश को अभी तक बचाने में कामयाबी हासिल की है। दूसरा यह कि भविष्य में खड़ी होने वाली चुनौतियों के लिए सरकार ने नेशनल हेल्थ सिस्टम के स्तर पर तैयारी कर ली है। ऐसा कहने के पीछे कुछ ठोस आधार हैं।

आंकड़ों से जाहिर होता है कि यदि दो चरणों का लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो देश में कोरोना संक्रमण की तस्वीर कुछ और होती। 24 मार्च को भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने की रफ्तार 21.6 फीसद थी, जो अब 10 फीसद से नीचे

आ चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आज भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक होती।

पिछले दो चरणों के लॉकडाउन की बड़ी सफलता यह भी रही कि देश कोरोना के 'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' की विभीषिका से बचते हुए कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाने में सफल रहा। जर्मनी के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने 1,000 कोरोना संक्रमितों की मौत तक 7 लाख से अधिक टेस्ट कर पाया है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जिस दिन 1,000 कोविड संक्रमितों की मौतें हुई थीं, उस दिन वह 5,59,468 टेस्ट कर पाया था। वहीं भारत ने इस स्तर तक पहुंचने तक 7 लाख 70 हजार से अधिक टेस्ट किये हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत की इस सफलता के पीछे बड़ा कारण लॉकडाउन सही समय पर लागू होना है। शुरूआती दिनों में भले ही टेस्ट की संख्या कम रही, लेकिन भारत ने जल्दी ही टेस्ट की गति को तेज कर लिया है। 1 मई की सुबह तक भारत ने कुल 9 लाख से अधिक टेस्ट किये हैं। इस दौरान देश में 304 सरकारी लैब तथा 105 प्राइवेट लैब बनकर भी तैयार हुए हैं।

गौर करने लायक तथ्य है कि 1 मई तक भारत में 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर, 500 से कम कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्ट तथा 800 से कम कोरोना मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ी है। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने इसको लेकर पर्याप्त तैयारियां की हैं। गत 22 अप्रैल तक ही देश में 724 कोविड अस्पताल, 12 हजार से अधिक वेंटिलेटर, 24 हजार आईसीयू बनाने में सरकार कामयाब हो चुकी थी। निश्चित ही इस संख्या में अबतक पर्याप्त इजाफा हुआ होगा। अगर पहले दो चरणों का लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना संक्रमितों की तुलना में इतनी पर्याप्त तैयारियां शायद संभव नहीं हो पाती।

सही समय पर सही कदम उठाने का एक लाभ यह भी हुआ कि भारत ने कोविड के इलाज के अनुकूल अपने चिकित्सा

संसाधनों को चिह्नित कर लिया। यही कारण है कि भारत में कोविड मृत्यु दर 4 फीसद के आसपास है, जबकि रिकवरी का अनुपात 25 फीसद से अधिक है। यह अनुपात गत 10 अप्रैल के बाद से लगतार बढ़ा है।

अब जब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन 3.0 घोषित हो गया है तो भावी स्थिति का आकलन किया जाना स्वाभाविक है। कोविड प्रभाव के आधार पर देश के क्षेत्रों को जोन में विभाजित करने का एक लाभ यह नजर आता है कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई और जनजीवन की सहूलियत, दोनों पर ध्यान दे सकेगी। सरकार के सामने देश की स्थिति की स्पष्ट तस्वीरें होंगी। एक तस्वीर वह, जहां उसे कोरोना मुक्ति को प्राथमिकता देनी है तथा दूसरी तस्वीर वो जहां जनसहूलियत के अन्य विषयों को पटरी पर लाने के लिए ध्यान देना होगा। ऐसे में देश के ग्रीन जोन वाले 319 जिलों में उपलब्ध प्रशासनिक व सामाजिक संसाधनों का उपयोग करके धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जल्दी शुरू किये जा सकते हैं। साथ ही रेड जोन वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक व सामाजिक संसाधनों का उपयोग वायरस से मुक्ति की दिशा में और अधिक तीव्रता से संभव हो सकेगा। कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने राज्यों से संवाद करते हुए स्पष्ट दृष्टि के साथ इस स्थिति से निपटने की नीति तैयार की है।

विपक्ष चाहें जो भी दलीलें दे लेकिन तथ्यों व आंकड़ों की कसौटी पर कोविड के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय खरे साबित हो रहे हैं। अनेक बार मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें समझने में विरोधी चूक कर जाते हैं। शायद इसबार भी लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़े करने वाले चूक ही कर रहे हैं।

(यह लेख पूर्व में द प्रिंट में प्रकाशित है।)

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं।)

कोरोना से संघर्ष में योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध किया है कि वे वास्तव में कर्मयोगी हैं

► बी. एम. सिंह

बी ते सोमवार की शाम एक दुखद खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के पिता का एक लम्बी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले मुख्यमंत्री योगी ने ये एलान किया कि लॉकडाउन की वजह से वह अपने पिता की अंतिम क्रिया में नहीं जा सकेंगे बल्कि प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के कल्याण के लिये अभी मोर्चे पर डटे रहेंगे।

अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय उनका बिलकुल निजी मामला है, लेकिन यह देखना होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते यह उनके लिए बिलकुल ही मुश्किल नहीं था कि उत्तराखंड कार से या हेलीकाप्टर से चले जाते, लेकिन योगी ने ऐसी घोषणा करके सिद्ध किया कि वह सही मामले में कर्मयोगी हैं।

उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना ने पैर पसारा है, योगी लगातार उससे लड़ने की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। देश में ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जो ज्यादातर वक्त हेल्थ वर्कर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ मशविरा करने में बिता रहे हों, लेकिन योगी ने ऐसा करके उन्होंने बाकी लोगों के सामने एक नजीर पेश की है।

योगी ने 11 सदस्यों की एक टीम बनाई जिससे कि इस संकटकाल में छात्रों से जुड़े मुद्दे, राशन-पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ सफाई और किसानों से जुड़ी समस्याओं

का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जा सके। योगी के इस कदम को केंद्र ने सराहा भी और उससे प्रभावित होकर ऐसी कमिटियाँ भी बनाई कि जिससे समाज के सभी वर्गों की परेशानियों का निराकरण हो सके।

योगी की कार्यशैली को इस उदहारण से समझा जा सकता है कि जब दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा में धकेले गए मजदूरों को रातों रात उन्होंने बसों के द्वारा उनके मंतव्य पर पहुंचवाने का काम किया। यह सहज नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीमा में हजारों मजदूर आ जायें और आपके पास रिएक्शन टाइम महज कुछ घंटे रहें, ऐसे में योगी न केवल निर्णय लेते हैं बल्कि उस पर तुरंत अमल भी करते हैं। योगी का सुप्रबंधन ही है कि उस दिन के बाद से अब तक कोई भी मजदूर प्रवासियों का संकट उत्तर प्रदेश की धरती पर देखने को नहीं मिला है।

चूँकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई दीर्घकालिक है, इसलिए योगी ने राज्य स्तर पर एक कोविड फण्ड बनाया है ताकि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा सके व अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त की जा सकें। इस फण्ड से कम से कम ऐसा तो होगा ही कि उत्तर प्रदेश की सरकार को राज्य स्तरीय ज़रूरतों के लिए काफी हद तक केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस फण्ड के जरिये वेंटीलेटर खरीद जा सकेगा, प्रोटेक्शन के लिए अलग से किट खरीदे जा सकेंगे और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ज़रूरी सुरक्षा व संसाधन

उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

लॉकडाउन चूँकि लम्बा खींच रहा है, ऐसे में यह ज़रूरी था कि उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे लोगों को सम्मान के साथ वापस लाया जा सके। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को, मजदूरों को वापस लाने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके उनको वापस लाने का काम किया, यह किसी भागीरथ प्रयास से कम नहीं था।

ज़ाहिर है, हमारे यहाँ जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें कुछ अधिकारी सिस्टम का फायदा उठाते हैं, योगी ने ऐसे अधिकारियों को भी किनारे लगा, चुस्त-दुरुस्त अधिकारियों को सामने आने का मौका दिया, जिससे सरकार के फैसलों पर वारित ढंग से अमल हो सके। जिला स्तर पर कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए योगी ने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि जिले की सीमा पूरी तरह से सील हो जायें।

कोरोना संकट के दौरान मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ऐसे में यह ज़रूरी था कि उनके हितों का ध्यान रखा जाय, अतः मजदूरों के खाते में 1000 रुपये जमा करवाने का काम योगी सरकार द्वारा किया गया, जिससे कम से कम उनके दैनिक रोजी-रोटी का प्रबंध हो सके।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश की सर्वाधिक आबादी वाला सूबा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश अगर आज कोरोना के केसों के मामले में काफी निचले पायदान पर है, तो इसमें योगी आदित्यनाथ की उपर्युक्त कार्यशैली और नेतृत्व ही कारण है। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना से संघर्ष में योगी ने सिद्ध किया है कि वे वास्तव में कर्मयोगी हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा, तब कांग्रेस केंद्र सरकार से लड़ रही है

► रमेश कुमार दुबे

दे श की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस गंभीर वैचारिक द्वंद्व में फंस चुकी है। अनुच्छेद-370 समाप्ति करने, नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर तो उसके नेताओं में परस्पर विरोध था ही, अब कोरोना संकट में भी पार्टी के अंतर्विरोध उभरकर सामने आ रहे हैं।

पार्टी के कई मुख्यामंत्री और वरिष्ठ नेता जहां लाकडॉउन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही हैं। मोदी विरोध की धुन में कई कांग्रेसी नेता इस जमीनी हकीकत को भी मानने को तैयार नहीं हैं कि जिन देशों ने अर्थव्यगवस्थात को वरीयता देते हुए लाकडॉउन में देरी या लाकडॉउन नहीं किया उन्हें जानमाल का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन देशों में जान भी गया जहान भी चरितार्थ हो रहा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 के शुरू में कहा था कि पार्टी संकट के इस दौर में दलगत भावना से उपर उठकर मोदी सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। लेकिन वही राहुल गांधी अब लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं और केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते को रोके जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी को देखते भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो कांग्रेस केवल केंद्र सरकार के

खिलाफ लड़ रही है।

देखा जाए तो कोविड 19 संक्रमण मामले में सरकार के कामकाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे वैश्विक समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सक्रियता ने कांग्रेसी नेताओं को बौखलाहट से भर दिया है। तभी तो जब प्रधानमंत्री लोगों से कोविड-19 से लड़ने वालों के लिए ताली, थाली, शंख बजवा रहे थे या फिर दीया जलवा रहे थे तब सबसे ज्यादा छटपटाहट कांग्रेसी नेताओं में ही थी। कमोबेश यही हाल दूसरे राजनीतिक दलों का है।

दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा की इस घड़ी में सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। वे लगातार विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद करने, कोविड-19 का संक्रमण रोकने में सहयोग करने, मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सचिवों, उच्च स्तरीय समितियों से चर्चा करने, मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट लेने, दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों, मिशनों से संवाद करते रहने के साथ-साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक निश्चित अंतराल पर चर्चा करके राय लेते हैं।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं की राय लेने, कांग्रेस अध्याक्षा सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, क्षेत्रीय दलों के नेताओं से कोविड-19 संक्रमण रोकने में सहयोग मांगने में नहीं चूके। प्रधानमंत्री ने इससे भी आगे बढ़कर वह देश के

खेल जगत, बालीवुड, अन्य कलाकारों, प्रोफेशनलों के भी संपर्क किया। वह देश की जनता के साथ दुःख दर्द साझा करते हुए जुड़ते हैं और देश की पंचायतों से भी संवाद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री की यही सक्रियता कांग्रेस को अपच कर रही है। दरअसल सत्ता कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। इसीलिए कांग्रेस की हर गतिविधि सत्ता को ध्या

न में रखकर होती है। यही कारण है कि संवेदनशील मुद्दों पर कई बार कांग्रेस वैचारिक रूप से पंगुता वाली स्थिति में आ जाती है। इसी विचारशून्यता के कारण पार्टी का दायरा सिमटता जा रहा है। इसके बावजूद भी पार्टी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं कर रही है।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

बेहतर एवं सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के चलते मेडिकल टूरिज्म का हब बनने की ओर बढ़ता भारत

▶ प्रह्लाद सबनानी

विश्व के कई देशों यथा चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, अमेरिका एवं अन्य कई यूरोपीयन देशों में तो कोरोना वायरस ने सचमुच में ही महामारी का रूप ले लिया है क्योंकि इन देशों में मरीजों की संख्या अब लाखों में पहुंच गई है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या 18.27 लाख का आंकड़ा पार कर गई है एवं 1.12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में चूंकि केन्द्र सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को शुरू से ही समझा एवं सुधारामक उपायों की घोषणा समय समय पर की जाती रही जिसके चलते भारत में स्थिति अभी भी नियंत्रण में बनी हुई है।

कोरोना वायरस के चलते, जब विकसित देशों

को अपने यहां दवाईयों की कमी महसूस हुई तो इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत से अपील की कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवा तुरन्त उपलब्ध कराई जाय। भारत ने भी इन सभी देशों को उक्त दवा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाया एवं उन्हें उक्त दवाई उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कर दी है।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर दृष्टि डालें तो हाल ही के वर्षों में, भारत ने न केवल फार्मा क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास किया है बल्कि विदेशी नागरिकों के इलाज के लिये भी भारत एक खास जगह बनता जा रहा है।

मेडिकल सुविधाओं के मामले में भारत विश्व के कुछ

चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। विदेशी नागरिक भारत में अब केवल घूमने के मकसद से नहीं आ रहे हैं बल्कि अपना इलाज कराने भी आ रहे हैं। भारत सरकार भी चिकित्सा क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की ओर लगातार काम कर रही है। इसमें चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही तकनीकी सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है।

हर साल जटिल बीमारियों का इलाज कराने कई हजारों विदेशी नागरिक भारत आ रहे हैं। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा, इलाज के लिहाज से, पसंद किया जाने वाला देश बन गया है। वर्ष 2013 में भारत ने जहां केवल 59,129 मेडीकल वीजा जारी किये थे, वहीं 2014 में 75,671, 2015 में 134,344, 2016 में 201,099 एवं 2017 में 495,056 मेडीकल वीजा जारी किये गये।

विकसित देशों में बीमारियों का इलाज बहुत मंहगा है। भारत में उक्त राशि की तुलना में यह केवल 20 से 30 प्रतिशत तक की राशि के बीच ही हो जाता है। अतः भारत में मेडीकल टूरिज्म बढ़ रहा है। पड़ोसी देशों के नागरिक भी गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु भारत का रुख करते हैं। 2016 में बंगलादेश के एक लाख लोगों को मेडीकल वीजा जारी किया गया था। अफ़गानिस्तान के 34,000 लोगों को, ईराक के 13,465 लोगों को, ओमान के 12,222 लोगों को, नाइजीरिया के 4,359 लोगों को एवं उजबेकिस्तान के 4,420 लोगों को मेडीकल वीजा जारी किया गया था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के लोग भी अब भारत में इलाज के लिये आ रहे हैं।

भारत ने 2014 में अपनी वीजा नीति को उदार बनाया था जिसका लाभ अब मेडीकल क्षेत्र को भी मिल रहा है। हर साल मेडीकल वीजा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के कई निजी अस्पताल विदेशी नागरिकों

को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों की तुलना में भारत में इलाज बहुत सस्ता है। वैश्विक स्तर की चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में उपलब्ध हैं। उच्च प्रशिक्षित डाक्टर और पेशेवर स्वास्थ्य कर्मचारी भारत में उपलब्ध हैं। परिवहन, होटल, खानपान पर होने वाले खर्च भी भारत में काफ़ी कम हैं।

आधुनिक चिकित्सा तकनीक और उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही आयुर्वेद और योग जैसी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियां भी भारत में उपलब्ध है। पूरे एशिया में इलाज की लागत सबसे कम भारत में आती है। मिडिल ईस्ट, अफ़्रीका, यूरोप से इलाज कराने लोग भारत आ रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत का हिस्सा करीब 18 प्रतिशत है। 2020 तक भारतीय टूरिज्म का कारोबार 9 अरब डालर होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

केन्द्र सरकार अब देश के नागरिकों को भी सस्ती दरों पर दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में साढ़े छह करोड़ लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं। गरीबी बढ़ाने वाले इस इलाज में एक बड़ा योगदान महंगी दवाओं और महंगे चिकित्सा उपकरणों का रहा है।

स्पष्ट है, महंगा इलाज गरीबी मिटाने के संकल्प में एक बड़ी बाधा रहा है। परंतु, लंबे अरसे की उपेक्षा के बाद, अब केन्द्र सरकार गरीबों के लिए जहां आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है, वहीं सभी लोगों के लिए सस्ताव इलाज उपलब्ध कराने का बीड़ा भी केन्द्र सरकार ने उठाया है। इसके लिए केन्द्र सरकार गांव-गांव में आधुनिक स्वाकस्ट्रिड सुविधाओं का विकास कर रही है। हर तीन लोक सभा सीटों पर एक

मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है ताकि देश में मेडिकल सीटों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।

देश की जनता को, महंगी दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार देश भर में जन औषधि केंद्रों की स्थापना कर रही है। यहां, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बाजार दर से 50-60 प्रतिशत तक सस्ते मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर की जो दवा बाजार में 6500 रुपये की मिलती है वही दवा जन औषधि केंद्रों पर 850 रुपये में उपलब्ध है।

इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं दी जाती हैं जो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही कारगर होती हैं। केन्द्र सरकार ने एक हजार से अधिक जरूरी दवाओं के दामों को नियंत्रित किया है जिससे आम आदमी को हर साल 12500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। स्पष्ट है, केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार की इस मुहिम से सभी नागरिकों के लिए सस्ताक व सुगम इलाज अब एक वास्तविकता बनता जा रहा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट के इस कठिन काल से और मजबूत होकर निकलेगा भारत!

▶ पीयूष द्विवेदी

क हा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के चरित्र और उसके नेतृत्व की वास्तविक पहचान संकटकाल में ही होती है। देखा जाए तो वर्तमान में किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं अपितु समूचे विश्व के समक्ष ऐसा ही एक संकटकाल उपस्थित है। कोरोना वायरस जनित वैश्विक महामारी ने विश्व के छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष कठिन परीक्षा का एक ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया है, जिसमें विश्व के लगभग सभी नागरिकों सहित उनके नेतृत्वकर्ताओं के भी धैर्य, संयम, समझदारी और दूरदर्शिता की कठिन परीक्षा हो रही है। यह कहना अनुचित नहीं लगता कि इस कठिन काल के बीतने के पश्चात् वैश्विक राजनीति के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आने की संभावना है तथा इस

संघर्ष में राष्ट्रों का प्रदर्शन ही आगामी विश्व की राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करेगा।

अमेरिका जो विश्व का स्वघोषित दारोगा बना हुआ था, उसकी स्थिति इस महामारी में सबसे अधिक दयनीय और चिंताजनक हो रही है। विश्व के कुल कोरोना संक्रमितों में एक तिहाई संक्रमित अकेले अमेरिका के हैं और इस संक्रमण से हुई मौतों में भी एक चौथाई से अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। ये आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ भी रहा है और विश्व का ये महाशक्ति राष्ट्र अपने लोगों को मरते देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा।

ये स्थिति केवल अमेरिका की ही नहीं है, अपितु कभी विश्व को अपने शासन में रखने वाला ब्रिटेन आज अपने

प्रधानमंत्री को तक इस महामारी के संक्रमण से नहीं बचा पाया। यह संतोषजनक है कि बोरिस जॉनसन स्वस्थ हो गए हैं, परन्तु मात्र साढ़े छः करोड़ के लगभग आबादी वाले ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या का लाखों में पहुँच जाना भयभीत करने के साथ-साथ चकित भी करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले विश्व में शीर्ष पर रहने वाले स्पेन और इटली की स्थिति भी हमारे सामने है। रूस और फ्रांस जैसी महाशक्तियाँ भी इस महामारी के समक्ष बेबस नजर आ रहीं, तो वहीं चीन विश्व को इस संकट में डालकर अब इसका व्यापारिक लाभ लेने में जुटा हुआ है।

समग्रतः इस पूरे परिदृश्य में हम विश्व के इन कथित महाशक्ति राष्ट्रों के सामर्थ्य और चरित्र दोनों को देख सकते हैं। इस कठिन काल में भी कोई अपना व्यापार बढ़ाने में जुटा है, तो कोई दूसरे पर आरोप लगाने में मशगूल है। वस्तुतः इनमें कोई एक ऐसा राष्ट्र नहीं दिखता जिसका महाशक्तित्व विश्व को वह मार्ग सुझा सके जिसके द्वारा कोरोना के संकट से निपटा जा सकता है। परन्तु, इन सबके बीच यह कार्य भारत ने किया है। भारतीय नेतृत्व से लेकर नागरिकों तक ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस सूझबूझ, समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस महामारी को अपने यहाँ भयानक रूप में पाँव पसारने से रोका है, वो कहीं न कहीं आज पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन चुका है।

गौर करें तो जब विश्व के उक्त महाशक्ति देश कोरोना को हल्के में ले रहे थे तथा नागरिकों के जीवन से अधिक अर्थव्यवस्था की चिंता में थे, भारत ने तभी से देश में इसकी आहट को भांपते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक हो या 22 मार्च को हुआ जनता कर्फ्यू हो अथवा 24 मार्च को पहले इक्कीस दिन और फिर उसके पश्चात् 14 अप्रैल को 3 मई तक के लिए घोषित लॉकडाउन, इन निर्णयों ने स्पष्ट किया कि भारत की

सरकार के लिए अपने नागरिकों का जीवन सर्वप्रथम है। लॉकडाउन का निर्णय उचित था, परन्तु इतने विशाल और सघन जनसंख्या वाले देश में इसे लागू करने की अनेक चुनौतियाँ थीं और वो सामने आईं भी।

दैनिक आय पर निर्भर मजदूर वर्ग के समक्ष भुखमरी का संकट उपस्थित न हो इसके लिए सरकार ने वित्तीय घोषणाएं की तथा अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी बीमा का ऐलान किया। ऐसे और भी कई निर्णय लिए गए।

इन प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला यह देश कोरोना संक्रमितों के मामले में शीर्ष के दस देशों से बाहर है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के अभी इस महामारी के खतरनाक प्रभाव से बचे होने में नागरिकों के सहयोग के साथ-साथ हमारे नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति, सूझबूझ और दूरदर्शितापूर्ण कार्यशैली ही कारण है।

भारतीय नेतृत्व की सफलता का प्रमाण हाल ही में सामने आए एक वैश्विक सर्वेक्षण से भी मिल जाता है। अमेरिका की एक डाटा इंटेलिजेंस कंपनी 'मॉनिंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस' ने हाल ही में कोरोना वायरस की लड़ाई से संबंधित दुनिया भर के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में दुनिया के सभी बड़े नेताओं की रेटिंग भी जारी की गई है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ाई में विश्व के सभी बड़े नेताओं के बीच सबसे ऊपर स्थान दिया गया है।

इस रेटिंग को सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध लिए गए फैसलों और काम करने के तरीकों तथा लोगों के अपने नेतृत्व पर विश्वास जैसी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सब कसौटियों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल साबित हुए हैं और 68 अंकों के साथ सूची में शीर्ष पर उपस्थित हैं। स्पष्ट है कि इस संकटकाल

में भारतीय नेतृत्व विश्व का ध्यान खींच रहा है और विश्व भारतीय नेतृत्व की निर्णय क्षमता और प्रबंधन कुशलता को एक उदाहरण की तरह ले रहा है।

इतना ही नहीं, विशेष यह भी है कि एक तरफ जहां पड़ोसी चीन इस आपदा का व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुचित इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहा, दूसरी तरफ भारत ने कोरोना से लड़ाई में केवल अपनी रक्षा ही नहीं की है, अपितु विश्व के अन्य देशों को भी सहयोग दिया है। अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों को भारत ने कोरोना

के उपचार हेतु प्रयोग हो रही दवा हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन देकर उनका सहयोग किया है। ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि इस संकटकाल में न केवल भारत ने अपने संकटकालीन उत्तम प्रबंधन व नीति नियोजन का परिचय दिया है, वरन उसने विश्व को कुटुंब समझने वाले सनातन दर्शन को भी चरितार्थ करके दिखाया है। आज ये जो कुछ घट रहा है, आने वाले कल की इबारत इसीपर लिखी जाएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट : मोदी के जिन कार्यों की विश्व प्रशंसा कर रहा, कांग्रेस उनमें खोट निकालने में लगी है

► आदर्श तिवारी

दे श कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इस युद्ध में सभी मिलकर लड़ें क्योंकि सामूहिक प्रयास और एकजुटता से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की एकजुटता लाने के प्रयास लगातार किए हैं। इस लड़ाई में आम जनमानस का जो सहयोग मिल रहा है वह भी अभूतपूर्व है। एक सर्व समावेशी सरकार के मानकों पर इस समय नरेंद्र मोदी सरकार को परखें तो वह शत प्रतिशत खरी उतरी है।

इस लड़ाई में सरकार के प्रयासों, सबकी सहभागिता और सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक पटल पर भारत की सराहना हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक तौर पर एक अलग ही पहलू उभरकर सामने आया है। जैसे-जैसे केंद्र सरकार फैसले लेती जा रही है और उसको सराहा जाने लगा है। कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पा रही है। लिहाजा आज कांग्रेस इस लड़ाई में सतही राजनीतिक हथकंडे अपनाने लगी है।

जो लड़ाई सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक

महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा के आधार पर लड़नी चाहिए, उसमें अब कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों को प्रमुखता देने लगी है। विगत दिनों राहुल गाँधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके लॉकडाउन को समस्या का हल नहीं माना, बल्कि इस एक पॉज बटन की संज्ञा दी। अब यहाँ दो बातें निकलकर आती हैं पहला, जब ये समस्या का हल नहीं है फिर कांग्रेसशासित राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय का विरोध करने की बजाय पहले ही अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि क्यों बढ़ा दी?

कोविड-19 की इस लड़ाई में कांग्रेस के अनेक नेताओं के विचारों में घोर विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। ज्ञातव्य हो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय का खुलकर स्वागत किया था जबकि कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने देश की जनता पर लॉकडाउन को थोपा है।

क्या यह सही नहीं है कि लॉकडाउन से पहले नए केस की औसत ग्रोथ रेट 35% थी जो घटकर 15% तक आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता तो भारत में 15 अप्रैल तक आठ लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की गिरफ्त में होते जो आज महज 22-23 हजार के आसपास हैं।

भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का औसत भी क्रमशः बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े में सुधार होना भारत के लिए अच्छा बात है। आज लगभग 20% लोग इस बीमारी से लड़कर जीत रहे हैं। एक और सवाल जांच क्षमता को लेकर उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि आज हमारे पास 287 जाँच लैब हैं, पांच लाख के करीब हमने टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगले

माह तक हमारी जांच क्षमता एक लाख तक पहुँच जाएगी।

लॉकडाउन में गरीब, मजदूरों को कोई तकलीफ न आए, भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए इस उद्देश्य से केंद्र सरकार काम कर रही है। बावजूद इसके कभी गरीबों को भड़काने तो कभी सरकार के कार्यों पर फिजूल में सवाल खड़ा करने का काम कांग्रेस द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन को समझे बगैर कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि राहुल ने कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होने की जो बात कही थी, वह महज एक राजनीतिक पाखंड था।

जहाँ तक गरीबों और किसानों का सवाल है, सरकार हर संभव गरीबों तक पहुँच रही है। किसानों-मजदूरों के हक का पैसा बगैर बिचौलियों के उनके खाते में पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और उज्ज्वला योजना के तहत राशन और सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8.89 करोड़ परिवारों को 17,793 करोड़ रुपये भेजा जा चुका है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ लोगों को 31,235 करोड़ की वित्तीय मदद की जा चुकी है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का यह चरित्र रहा है जब भी देश पर संकट आया है वह इस संकट से लड़ने की बजाय एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने लग जाती है। याद करिये जब उरी अथवा पुलवामा हमला हुआ कांग्रेस ने समय की नजाकत को समझते हुए भी आतंकियों पर हमलावर होने से पहले सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया था।

सर्जिकल अथवा एयरस्ट्राइक के समय जब देश में मोदी सरकार की वाहवाही हो रही थी, तो कांग्रेस परेशान होने लगी और अंत में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सेना के सौर्य और पराक्रम पर संदेह जताते हुए स्ट्राइक के सुबूत माँगना

शुरू कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं कि विपक्षी दल होने के नाते सरकार की नीतिगत आलोचना करना कांग्रेस का कर्तव्य है, परंतु संकट के समय सहयोग की बजाय बेमतलब ही सरकार की टांग खींचना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

अब सवाल यह उठता है कि इसके पीछे की मंशा क्या होती है? दरअसल कांग्रेस इस आलोचना के जरिये यह प्रदर्शित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह विफल है और कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही है जो जनहित में हो। इन सबका लब्बोलुआब यही होता है कि मृतप्राय अवस्था में पड़ी कांग्रेस को लेकर जनता में भरोसा पैदा हो और उसे संजीविनी मिल जाए। दुर्भाग्य से कांग्रेस के ये पैतरे हमेशा जनभवनाओं के प्रतिकूल होते हैं, जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है। आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार जनभावनाओं की उपेक्षा बार-बार करते आ रहे हैं और हरबार उन्हें उनकी ही रणनीति ने परास्त किया है। इन सब के बावजूद वह सबक लेने को तैयार नहीं हैं और कोरोना के इस संकटकाल में भी वही गलती दुहरा रहे हैं।

कांग्रेस की अनर्गल आलोचना से इतर वस्तुस्थिति ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 से लड़ने की नीतियों की प्रशंसा विश्व भर में हो रही है। अमेरिका की रिसर्च कम्पनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलीजेंस ने विश्व भर में किए अपने सर्वे में पाया है कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 अंको के साथ पहले नम्बर पर हैं।

ज्ञातव्य हो कि यह सर्वे विश्वभर के नेताओं द्वारा कोरोना के संकटकाल में कार्य करने की क्षमता एवं लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर किया गया है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोदी सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंदों के हित में लिए जा रहे निर्णयों के साथ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का भी स्वागत किया है।

सरकार द्वारा 1.70 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज एवं आरबीआई द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों पर आइएमएफ ने भी केंद्र सरकार की सराहना की है। बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की भरपूर सराहना की है।

लॉकडाउन में सभी को कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार के प्रयासों की सराहना वैश्विक स्तर पर होने के बावजूद कांग्रेस द्वारा इस कठिन चुनौती काल में सरकार को नाकाम कहना और राजनीतिक बयानबाजी करना छिछली राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर समय रहते कांग्रेस ने सबक नहीं लिया तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक, पठानकोट हमले पर बयानबाजी के जो दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे, शायद उससे भी अधिक खामियाजा इस गलती के लिए भुगतना पड़े।

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं।)

कोरोना संकट : डॉ. मोहन भागवत ने अपने संबोधन में दिखाई नई राहें

► संजय द्विवेदी

को रोग संकट से विश्व मानवता के सामने उपस्थित गंभीर चुनौतियों को लेकर दुनिया भर के विचारक जहां अपनी राय रख रहे हैं, वहीं दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के संवाद ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहने को तो डा. भागवत अपने संगठन के स्वयंसेवकों से संवाद कर रहे थे लेकिन इस संवाद के निहितार्थ बहुत विलक्षण हैं। उनके संवाद में देशभक्ति, मानवता और भारतवासियों के प्रति प्रेम के साथ वैश्विक आह्वान भी था कि अब विश्व मानवता के लिए भारत अपने वैकल्पिक दर्शन के साथ खड़ा हो। उन्होंने साफ कहा कि हमें संकटों को अवसर में बदलने की कला सीखनी होगी।

एक राष्ट्र-एक जन

सेवा के कामों में जुटे अपने स्वयंसेवकों से उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए कोई पराया नहीं है। एक अरब तीस करोड़ भारतवासी उनका परिवार हैं। भाई-बंधु हैं। इसलिए सेवा की जरूरत जिन्हें सबसे ज्यादा है, उन तक मदद किसी भेदभाव के बिना सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। उनकी इस राय के खास मायने हैं। उनका साफ कहना था कि भय और क्रोध से अतिवाद पैदा होता है। हमें हर तरह के अतिवाद से बचना है और भारत की सामूहिक शक्ति को प्रकट करना है।

उनके संवाद में देश के सामने उपस्थित चुनौतियों का सामना करने और उससे आगे निकलने की सीख नजर आई। उनके समूचे भाषण में भय और क्रोध शब्द का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया और इन दो शब्दों के आधार होने वाली प्रतिक्रिया से सतर्क रहने को कहा। उनका कहना था कि समाज के अग्रणी जनों को ऐसे अवसरों पर अपने लोगों को संभालना चाहिए ताकि प्रतिक्रिया के अतिवादी रूप सामने न आए।

नर सेवा-नारायण सेवा

सेवा संघ के मुख्य कामों में एक है। देश के हर संकट, दैवी आपदाओं और दुर्घटनाओं में संघ के स्वयंसेवक बिना प्रचार की आस किए सेवा के लिए आगे आते हैं। उसके सेवा भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन प्रत्यक्ष सेवा के काम से जुड़े हैं। इसके अलावा संघ के प्रत्येक आनुषांगिक संगठन के अपने-अपने सेवा के काम हैं। उन्होंने सेवा के काम में प्रत्यक्ष लगे कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि वे सावधानी के साथ अपना काम करें ताकि काम के लिए वे बचे रहें। कोई छूट न जाए और अपनत्व की भावना का प्रसार हो।

उन्होंने कहा कि हम उपकार नहीं, सेवा कर रहे हैं इसलिए इसे गुणवत्तापूर्ण ही होना होगा। प्रेम, स्नेह, श्रेष्ठता और अपनत्व की भावना से ही सेवा स्वीकार होती है। हमें अच्छाई का प्रसार करना है और भारतीयता के मूल्यों को

स्थापित करना है। समाज के संरक्षण और उसकी सतत उन्नति ही हमारे लक्ष्य हैं।

स्वावलंबी भारत-सशक्त भारत

अपने संबोधन में डा. भागवत ने स्वदेशी और स्वालंबन की आज फिर बात की। उनका कहना था कि जो कुछ हमारे पास उसे अन्य से लेने की आवश्यकता क्या है। इसके लिए हमें स्वदेशी का आचरण करते हुए स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। जिसके बिना हमारा काम चल सकता है उसे विदेशों से लेने की आवश्यकता क्या है। विदेशों पर निर्भरता को कम करने और समाज का स्वालंबन बढ़ाने पर उनका खासा जोर था।

वे यहीं नहीं रुके उन्होंने रासायनिक खेती के खतरों की तरफ इशारा करते हुए जैविक खेती और गो-पालन पर भी जोर दिया। संघ लंबे समय से स्वदेशी की बात करता आ रहा है किंतु सत्ता की राजनीति मजबूरियों और राजनीति के खेल में उसकी आवाज अनसुनी की जाती रही है। कभी नीतियों के स्तर पर तो कभी विश्व बाजार के दबावों में। कोरोना संकट के बहाने एक बार फिर संघचालक ने स्वदेशी के आह्वान को मुखर किया है तो इसके विशेष अर्थ हैं।

संतों की हत्या पर जताया दुख

अपने संवाद में डा. भागवत पालघर में दो संतों की हत्या पर दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य को समझकर इसकी पुनरावृत्ति रोकनी चाहिए। क्योंकि संत तो सब कुछ छोड़कर समाज के लिए निकले थे उनकी हत्या का कोई कारण नहीं है।

नागरिक अनुशासन ही देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। राजनीति को स्वार्थ से अलग कर उसे समाज केंद्रित बनाने पर जोर देते हुए उनका कहना था कि आज हमें पर्यावरण, जीवन और मानवता तीनों के बारे में सोचने की जरूरत है। डा. भागवत के व्याख्यान की मुख्य बातें सही मायने में एक जीवंत समाज बनाने की भावना से भरी-पूरी हैं। उनकी सोच का भारत ही अरविंद, विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों का भारत है।

कोरोना संकट में हुए इस व्याख्यान के बहाने डा. भागवत ने संघ की सामाजिक, सांस्कृतिक भूमिका का खाका खींच दिया है। स्वयंसेवकों के सामाजिक उत्तरदायित्व और देश तोड़क शक्तियों के मंसूबों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने भय और क्रोध के आधार पर सृजित होने वाले अतिवाद को बड़ी चिंता से प्रकट किया। उनके संबोधन से साफ है कि संघ समाज में अपनी भूमिका को ज्यादा व्यापक करते हुए अपने सरोकारों को समाज के साथ जोड़ना चाहता है।

इस बार गर्मियों में संघ के प्रशिक्षण शिविर भी स्थगित हैं इसलिए स्वयंसेवकों के सामने इस संदेश पाथेय से करने के लिए काफी कुछ होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि संघ अपने विविध संगठनों के माध्यम से सेवा और देश के सशक्तिकरण के प्रयासों को व्यापक बनाने में सफल रहेगा। साथ ही उसके संकल्पों और कार्यों को सही संदर्भों में समझा जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट : प्रधानमंत्री के सार्थक आह्वान पर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

► सुयश मिश्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल, रविवार को रात्रि नौ बजे नौ मिनट तक देशवासियों से एक दीया-मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील क्या कर दी कि देश की मोदी विरोधी राजनीति में जलाजला सा आ गया। सबसे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया पर आकर घोषित किया कि वे दिया नहीं जलाएंगे।

उनके बाद महाराष्ट्र से शिवसेना नेता संजय राउत, म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आदि अन्य नेताओं ने भी दिया जलाने वाले संदेश पर तंज कसे। शशि थरूर ने तो नौ के अंक को ही हिंदू धर्म से जोड़ते हुए सांकेतिक भाषा में इसे भी हिंदुत्व का विस्तार बताने की कोशिश कर डाली। विपक्ष की मोदी विरोधी राजनीति का यह रूप उसके बौद्धिक दिवालियापन को ही दर्शाता है।

रेखांकनीय है कि मोदी के ताली-थाली बजाने वाले बयान पर पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, किंतु क्या हुआ? सारे देश ने मोदी के संदेश का सम्मान किया। विदेशों में मोदी के इस प्रयत्न की प्रशंसा हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने भी मोदी का अनुकरण करते हुये तालियाँ बजा कर महामारी से जूझ रहे अपने लोगों का उत्साहवर्द्धन किया।

अब फिर देश की अधिकांश जनता दीप जलाकर, प्रकाश करके अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करेगी और

विश्व फिर मोदी के इस प्रयास की सराहना करेगा। ऐसी स्थिति में विपक्ष के इन विरोधी बयानों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर भी विपक्ष उसका विरोध कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ सकारात्मक करने को, जनता को कोई रचनात्मक संदेश देने को कुछ है ही नहीं।

विरोधियों का यह कहना सच है कि ताली-थाली बजाने या दीपक, मोमबत्ती आदि से प्रकाश करने से कोरोना नहीं मरेगा। उसे समाप्त करने के लिए, इस महामारी पर विजय पाने के लिए वैज्ञानिक चिकित्सकीय प्रयत्न करने होंगे। हमारे प्रधानमंत्रीजी भी यह बात जानते हैं। इसीलिए देश का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेशों के मुख्यमंत्री चाहे वे किसी भी दल के क्यों ना हों, अपने दायित्वों के निर्वाह में कहीं पीछे नहीं हैं।

इस देश की केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर दिन-रात काम कर रही हैं। फिर भी विपक्षी बयानवाजी कहीं ना कहीं इन सब की मेहनत पर पानी फेरने वाली समाज-विरोधी मानसिकता को दर्शा रही है। ये नेता अपने समर्थकों को 5 अप्रैल को प्रकाश ना करने का अप्रत्यक्ष संदेश प्रसारित कर जनता की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक ओर देशवासी एकजुट होकर हर स्तर पर इस दुर्जेय लड़ाई को जीतने में जुटे हैं वहां देश के शीर्ष नेतृत्व में स्वयं को विपक्ष का बड़ा नेता समझने

वाले ये लोग अकारण विरोध प्रकट कर यह प्रचारित करने में व्यस्त हैं कि वे मोदीजी के साथ नहीं हैं। वे राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में भी पहले विपक्षी हैं और संवैधानिक रीति से भारी बहुमत से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के संदेश का सम्मान करना अपना कर्तव्य नहीं समझते।

देश के प्रधानमंत्री ने घोर अंधकार में प्रकाश दर्शाने, दीप जलाने का जो संदेश दिया है वह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों बार सड़कों पर मशाल जुलूस, कैंडल मार्च निकलते रहे हैं लेकिन तब कभी भी, कहीं भी, किसी ने भी इनकी आवश्यकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया। अब क्यों लगाया जा रहा है? वह भी कुछ विशेष दलों के विशिष्ट जनों द्वारा- यह विचारणीय है। इससे प्रश्नचिन्ह लगाने वालों की नीयत पर ही अधिक संदेह होता है।

वास्तव में नारे, रैली-जुलूस, धरना-प्रदर्शन यह सब एकजुटता और संगठन-शक्ति प्रदर्शित करने के कारगर उपाय हैं। इसलिए सामाजिक-राजनीतिक मामलों में इनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। मशाल-जुलूस, कैंडल मार्च, दीप आदि का आयोजन भी कार्यकर्ताओं में आशा और उत्साह का संचार करने के लिए होता है। इस

समय यह संदेश कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के घोर अंधकार में भी आशा की किरण दर्शाने के लिए किया गया सुविचारित आह्वान है। कोरोना की आपदा में घर में रहते हुए लोग प्रकाश करके एकता का संदेश दे सकते हैं, इसके विरोध का कोई अर्थ नहीं है।

देश की जनता में निराशा एवं नकारात्मक भावना न आए, उसे अपनी संगठित शक्ति का अनुभव हो; वह सकारात्मक ऊर्जा से भर कर इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए और भी अधिक शक्ति लेकर आने वाले समय में विजय प्राप्त करे इसलिए इस सहज साध्य सरल अनुष्ठान के आयोजन का महत्वपूर्ण संदेश देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया है। इस अवसर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संदेश का आदर करना विपक्ष का भी कर्तव्य है क्योंकि देशवासियों की सुरक्षा और देश के प्रधानमंत्री के संदेश का सम्मान पहले है, वोट बैंक की गहरी दलदल में धंसी संकीर्ण दलगत राजनीति बाद में।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

संघ प्रमुख के उद्बोधन के निहितार्थ बहुत गहरे हैं

► आदर्श तिवारी

दे श में कभी भी कोई बड़ा मामला आता है अथवा कोई विमर्श खड़ा होता है, तो देश का एक बड़ा तबका यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या राय है। आज भी यह प्रश्न उठ रहा है कि मौजूदा कोरोना के महासंकट से बाहर आने एवं वर्तमान में कोरोना वायरस से उपजी चुनौतियों से निपटने की दिशा में आरएसएस किस भूमिका का निर्वहन कर रहा है?

कोरोना के संक्रमण काल में ही तबलीगी जमात और पालघर में संतों की हत्या जैसी घटनाएँ भी सामने आईं जो मानवता को शर्मसार करने वाली थीं एवं यह संकेत दे रहीं थीं कि इस लड़ाई में ये कारक बड़ी बाधा बनकर चुनौतियों को और भी बड़ा करने वाले हैं। इन विषयों पर भी संघ के विचारों की तरफ लोगों की नजर थी। इन सब परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख द्वारा दिए गए सर्वसमावेशी उद्बोधन ने स्वयंसेवकों के साथ-साथ पूरे देश-समाज को भी धैर्यपूर्वक एकजुटता के साथ राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यबोध से परिचित करवाने का काम किया।

आरएसएस प्रमुख ने उपयुक्त समय पर आकर वर्तमान समय के सभी प्रमुख बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से अपने विचार रखे। अतः इस नाजुक हालत में संघ प्रमुख द्वारा दिए गए वक्तव्य के निहितार्थ गहरे हैं। मानवता की रक्षा और देश को एक सूत्र में पिरोने के लिहाज से यह उद्बोधन यकीनन एक सार्थक संवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश विभाजन के मंसूबों

को हवा देने वाले गिरोह को मोहन भागवत के वक्तव्य से जोरदार झटका लगा होगा।

बहरहाल, संघ सदैव युगानुकूल सकारात्मक पहल करके समाज में चल रही विषमताओं के बीच ऐसी दृष्टि देता है जिससे किसी भी बहस को नई और सकारात्मक दिशा मिलती है। कोरोना वायरस के कहर के बीच चल रही बहस को संघ ने फिर एकबार उस दिशा की तरफ मोड़ दिया है, जहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण की सार्थकता को बल मिलता है और मानवता विरोधी शक्तियों का दंभ छिन्न-भिन्न हो जाता है।

समझना आवश्यक है कि तबलीगीयों के मामले सामने आने के पश्चात इस विपत्तिकाल के समय ही सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की कोशिश की गई। समाज में वैमनस्यता फैलाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक कथित महिला एक्टिविस्ट ने गत दिनों एक विदेशी मीडिया समूह से कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका इरादा भारत को विखंडित करने वाला था।

एक समुदाय के मन में भारत सरकार और आरएसएस को लेकर भय का महौल खड़ा कर अपनी मंशा पर कामयाबी का परचम लहराने की चेष्टा थी। भारत में कोरोना की इस बड़ी लड़ाई में मिल रहे सबके सहयोग की चर्चा आज विदेशों में हो रही है, इसके बरक्स एक कल्पनाशील नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की गई।

गौरतलब है कि कथित एक्टिविस्ट ने कहा था कि भारत सरकार कोविड-19 का फायदा उठाकर मुसलमानों

को भड़काने की कोशिश में थीं और इसकी तुलना उन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान नाज़ी जर्मनी में यहूदियों से हुए बर्ताव से भी कर डाली। यह न केवल निंदनीय अपितु घातक वक्तव्य भी था। आगे वह आरएसएस से जोड़ते हुए कहती हैं कि इनके (आरएसएस) विचारक भारत के मुसलमानों को जर्मनी के यहूदियों जैसा मानते हैं।

अब हमें मोहन भागवत की बात को समझना चाहिए। अपने उद्बोधन में मोहन भागवत ने बिना किसी किन्तु-परन्तु के साफतौर पर कहा है कि 130 करोड़ लोग भारत माता के पुत्र हैं और अपने बंधू हैं। यह देश अपना है, इसलिए हम कार्य करते हैं। जो पीड़ित हैं, अपने हैं, हमें सबके लिए कार्य करना है।

भागवत ने अपरोक्ष रूप से उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो तबलीगी जमात की हरकतों के कारण समूचे समुदाय पर सवाल खड़े कर रहे थे। सर संघचालक ने कहा कि अगर कोई गलती करे तो उसमें पूरे समूह को लपेटना और उस पूरे समाज से दूरी बनाना ठीक नहीं है। इस उद्बोधन के मार्फत संघ प्रमुख का यह सन्देश बेहद महत्वपूर्ण था।

संघ के आलोचक संघ के उपर सबसे बड़ा आरोप साम्प्रदायिकता एवं समाज को तोड़ने का लगाते हैं। अब सर संघचालक के इस बयान के बाद उन्हें विवश होकर सोचना पड़ेगा कि समाज को तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? कहीं वह कारक उनके आसपास तो मौजूद नहीं हैं।

इस बयान के उपरांत उन कथित महिला एक्टिविस्ट द्वारा खड़ी की गई झूठ की दीवार भी जमींदोज हो गई है, परन्तु उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो कौन विचारक हैं जो उनके कहे अनुसार सोचते हैं क्योंकि संघ के मुखिया ने तो सार्वजनिक रूप से संघ की विचार दृष्टि सबके सामने रखकर उनके झूठे नैरेटिव को खंड-खंड कर दिया है।

बहरहाल, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धार्मिक एकता का सन्देश दे चुके थे और संघ प्रमुख ने भी एक बड़े

सांस्कृतिक संगठन के मुखिया होने के नाते एक समन्वयकारी विचार देशवासियों के समक्ष रखा।

गौरतलब है कि संघ के स्वयंसेवक देशभर में 55 हजार से अधिक स्थानों पर तीन लाख से अधिक की संख्या में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। संघ प्रमुख ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने लोगों की सेवा उपकार नहीं, वरन हमारा कर्तव्य है, जबतक हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते तबतक सावधानी नहीं छोड़नी है, भविष्य में राहत कार्य के साथ समाज को दिशा देने का कार्य भी हमें करना होगा।

इस अवसर पर संघ प्रमुख ने पालघर की घटना पर भी दुःख जाहिर करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए और धैर्य में रहकर सारी बातें सोचने और करने की सलाह दी। संघ प्रमुख ने समाज के प्रत्येक वर्ग के नेतृत्व को अपने-अपने समाज को भय और क्रोधवश होने वाले कृत्यों से बचाते हुए सकारात्मकता का वातावरण देश में बनाने का आह्वान किया।

लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात देश में आने वाली बड़ी चुनौतियों एवं अवसरों को भी रेखांकित करते हुए मोहन भागवत ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, प्लास्टिक से मुक्ति, जल एवं वृक्षों का संरक्षण तथा जैविक खेती से होने वाले लाभ की तरफ भी सबका ध्यान आकृष्ट किया।

गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में स्वावलंबन और आयुर्वेद जैसे विषयों का जिक्र किया था। संघ प्रमुख ने भी वैसी ही नीतियों पर की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अतः हमें इन विचारों से अवगत होने के पश्चात यह बात समझनी होगी कि भारत की आगे की नीति में इन बिंदुओं की झलक देखने को मिल सकती है और निःसंदेह ऐसी नीतियां संकट की इस घड़ी में विश्व को भी राह दिखाएंगी।

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च एसोसियेट हैं।)

कोरोना संकट की रोकथाम के लिए सभी मोर्चों पर तत्परतापूर्वक कदम उठा रही सरकार

► रमेश कुमार दुबे

पूरे विश्वा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चिकित्सा सुविधाओं के मामले में दुनिया भर में मानक स्थापित करने वाले इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों पर कोरोना कहर बरपा रहा है। दरअसल ये देश कोरोना संक्रमण के दूसरे व तीसरे चरण की भयावहता का अनुमान लगाने में विफल रहे। गौरतलब है कि जिन देशों ने कोरोना संक्रमण के दूसरे व तीसरे चरण के लिए व्यासपक तैयारी व बचाव किया उन देशों में संक्रमण भयावह रूप धारण नहीं कर पाया जैसे सिंगापुर और हांगकांग।

भारत में भी शुरूआती दो महीनों के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत धीमी गति से फैला। इसके बावजूद सरकार ने 2 फरवरी को कोरोना पर मंत्रिमंडलीय समूह (जीओएम) गठित कर दिया। सिनेमाघर, शापिंग मॉल, जिम बंद करा दिए गए। इतना ही नहीं कोरोना प्रभावित देशों के विदेश यात्रियों पर रोक लगाने के साथ-साथ होटलों में आयोजित किए जाने वाले सभी तरह के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।

कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के भयावह खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश की जनता से संकल्प और संयम अपनाने का आग्रह किया। इसके साथ-साथ उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में हिस्सेदारी लेने का

आह्वान किया जो कि पूरी तरह सफल रहा।

दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 21 दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा करते हुए लोगों से अपील की कि किसी भी कीमत पर घर के बाहर न निकलें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चले जाएंगे। इतना ही नहीं कई परिवार तो तबाह हो जाएंगे।

लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों, अंतर्राज्यीय बसों पर 14 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम से कम हो। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बताते हुए अंधविश्वास और अफवाहों से बचने की सलाह दी।

इसके बाद प्रधानमंत्री लॉकडाउन के देशव्यापी असर को कम करने और इलाज की समुचित व्यवस्था करने में जुट गए। सबसे पहला काम था जरूरी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कोरोना जांच की सुविधाओं का विस्तार। सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए 119 सरकारी लैबों को अधिकृत किया। इसके अलावा 35 निजी लैबों को भी अनुमति दी गई। निजी क्षेत्र के अस्पताल-लैब अपनी लूट के लिए कुख्यात रहे हैं इसीलिए सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्टों के लिए

अधिकतम 4500 रुपये की सीमा तय कर दी।

मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान देशवासियों विशेषकर गरीबों के समक्ष उपजे संकट का समाधान कैसे किया जाए। विशेषकर कमजोर वर्गों को तात्काकलिक राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दो हिस्सों में बांटकर रणनीति तैयार की गई है।

मोदी सरकार का सर्वाधिक बल तात्कारलिक राहत पहुंचाने पर है। इसके तहत सरकार 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को तीन महीने तक पांच किलो गेहूं-चावल और एक किलो दाल मुफ्त में वितरित करेगी। अगले तीन महीनों तक 20 करोड़ जन धन महिला खाता धारकों को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह आठ करोड़ उज्ज्वलेला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।

ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के असर को कम करने के लिए 13.62 करोड़ मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। तीन करोड़ बुजुर्गों, गरीब विधवाओं, विकलांगों के खाते में एक हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये की

पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह तक किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण कोष में जमा 31 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल 3.5 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के लिए होगा।

पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 प्रतिशत जमा धन या तीन माह का वेतन निकालने की सुविधा मिलेगी। महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए महिल स्वलय सहायता समूह की महिलाओं को दीन दयाल योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। यह लोन बिना किसी ब्यादज के दिया जाएगा

सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज में लगे डॉक्टरों, पैरा मेडिकलकर्मियों, चिकित्सा सेवाकर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर देने का फैसला किया है। इनमें आशा वर्कर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। इसका लाभ 20 लाख मेडिकल कर्मचारियों को मिलेगा।

समग्रतः मोदी सरकार का भारत में कोरोना जैसी आपदा से निपटने के लिए तत्परतापूर्वक सभी मोर्चों पर कदम उठाती नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रयास परिणाम में तब्दील हों और देश शीघ्र इस संकट से बाहर आए।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना, संवेदना और शिवराज : राजसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की हो रही पहल

► संजय द्विवेदी

मनुष्यों की तरह सरकारों का भी भाग्य होता है। कई बार सरकारें आती हैं और सुगमता से किसी बड़ी चुनौती और संकट का सामना किए बिना अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके हिस्से तमाम दैवी आपदाएं, प्राकृतिक झंझावात और संकट होते हैं। इस बार सत्तारूढ़ होते ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही संकटों से दो-चार हैं।

सत्ता ग्रहण करते ही वैश्विक कोरोना संकट ने उनके सामने हर मोर्चे पर चुनौतियों का अंबार ला खड़ा किया। यहीं पर अनुभव, राज्य की शक्ति और सीमाओं की समझ तथा समाज की चिंताओं का अध्ययन काम आता है। मध्यप्रदेश जैसे भौगोलिक तौर पर विस्तृत राज्य की चुनौतियां बहुत विलक्षण हैं। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उसके दोनों बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में कोरोना का संक्रमण विकराल दिखता है।

कोरोना का संकट एक ऐसी चुनौती है जिससे उबरना आसान नहीं है। सच तो यह है कि इस संकट के सामने दुनिया की हर सरकार खुद को विवश पा रही है। शपथ लेते ही जिस तरह खुद को झोंककर मप्र के मुख्यमंत्री ने अपनी दक्षता दिखाई वह सीखने की चीज है।

शिवराज सिंह की खूबी यह है कि वे अप्रतिम वक्ता और संवादकला के महारथी हैं। उनकी वाणी और कर्म में

जो साम्य है, वह उन्हें हमारे समय के राजनेताओं में एक अलग ऊंचाई देता है। उनकी खूबी यह भी है कि वे सिर्फ कहते नहीं हैं, खुद को उस अभियान में झोंक देते हैं। ऐसे में जनता, शासन-प्रशासन और सामाजिक संगठन उनके साथ होते हैं। कोरोना युद्ध में भी उन्होंने पहले तो लोगों को आश्चस्त किया कि वे लौट आए हैं। उनकी पुराना ट्रैक भी एक भरोसा जगाता है, जिसमें हर वर्ग की परवाह है, उनसे संवाद है और योजनाओं का सार्थक क्रियान्वयन है।

कोरोना योद्धाओं को दिलाया भरोसा

सरकार संभालते ही उन्होंने पहले तो कोरोना योद्धाओं को भरोसा दिया कि वे निर्भय होकर काम करें और उनकी चिंता सरकार पर छोड़ दें। यही कारण है कि डाक्टरों और पुलिस पर हमले और असहयोग करने वालों को उन्होंने जेल की सीखचों को भीतर डालकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कड़े कदम उठाए।

इसके बाद 'मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना' की शुरुआत की है जिसमें कोरोना की बीमारी में सेवा दे रहे कर्मियों के कल्याण की बात की गई। हर स्तर की चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मी, गृह विभाग, नगरीय निकाय के हर स्तर के कर्मी, निजी संगठनों के लोग व कोविड -19 से संबंधित सेवाओं में जुड़े हर पात्र कर्मी को इससे जोड़ा गया है। अपनी जान पर खेल लोगों की जान बचाने वाले लोगों के कर्तव्यबोध को जगाने का यह

अप्रतिम प्रयास है। इसके तहत सेवा के दौरान प्रभावित होने और जान जाने पर 50 लाख तक के मुआवजे का उनके आश्रितों के लिए प्रावधान है।

किसानों और श्रमिकों को प्रति संवेदना

किसानों पर अपने अनुराग के लिए शिवराज जाने ही जाते हैं। उन्हें किसानों के आंसू पोंछने और राज्य को कृषि क्षेत्र में ऊंचाईयों पर ले जाने का श्रेय है। किसानों को कष्ट न हो इसके लिए उनकी सरकार हर उपाय करती ही है। इसके साथ ही श्रमिकों के साथ उनकी संवेदना बहुज्ञात है। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने, कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने की पहल को इसी नजर से देखा जाना चाहिए।

शिवराज की सामान्य योजनाओं से समझा जा सकता है कि वे लोगों के कष्ट को समझते हैं तो सामाजिक सहभागिता के अवसर भी जुटाते हैं। महिलाओं से मास्क बनाने का आह्वान उनकी इसी सोच का परिचायक है जिसमें प्रति मास्क 11 रुपए दिए जाने का योजना है। इसे उन्होंने जीवनशक्ति योजना का नाम दिया है। किसानों के कल्याण और उन्हें सही मूल्य मिले इसके लिए सरकार शीघ्र ही मंडी एक्ट में संशोधन के लिए भी तैयार है। राज्य में किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ) को स्व-सहायता समूहों की तरह सशक्त बनाने की भी तैयारी है।

कोरोना को लेकर उनकी पूरी टीम पूरी सक्रियता से मैदान में है। वे ही हैं जो सरकार, संगठन, सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं, आम लोगों और समाज के हर वर्ग से संवाद करते हुए संकटों का हल निकाल रहे हैं। संवाद में उनका भरोसा है इसलिए वे राज्य स्तरीय समिति में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच, जबलपुर के लोकप्रिय चिकित्सक डा.

जितेंद्र जामदार आदि के साथ चर्चा कर राहें निकाल रहे हैं।

शिवराज जी की खूबी है कि वे अपनी सहजता, सरलता और भोलेपन से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं तो वहीं जब दृढ़ता का प्रदर्शन करना होता है, तो वे कड़े फैसले लेने में संकोच नहीं करते। इस बार सत्ता में आते ही उन्होंने जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लिए उसने यहसाबित किया कि वे शांतिकाल के नायक तो हैं ही, संकटकाल में भी अपना धैर्य नहीं खोते। असली राजनेता की यही पहचान है।

राज्य की आर्थिक चिंताओं से बड़ी इस राज्य के लोगों की जिंदगी है। तभी कोराना संकट से मुकाबले के प्रारंभ में ही मुख्यमंत्री ने कहा “जान है तो जहान है। आर्थिक प्रगति तो हम कभी भी कर लेंगे पर जीवन न रहा तो उसका क्या मतलब।” यह साधारण वक्तव्य नहीं है। यह एक तपे हुए राजनेता का बयान है, जिसके लिए अपने राज्य के लोग ही सब कुछ हैं। इसीलिए अब वे हैप्पीनेस फार्मूले की बात कर रहे हैं। उनके सपनों का आनंद मंत्रालय फिर से पुर्नर्जीवित होने जा रहा है। इसके तहत आनंद की गतिविधियों तो पूर्ववत चलेंगी ही, वर्तमान कोरोना संकट में इसके शिकार मरीजों को खुश रखने के भी प्रयास होंगे।

उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्यप्रदेश और देश कोरोना संकट से जीत पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण बनेगा। उसके द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं एक उदाहरण बनेंगी। जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आनंद और सामाजिक सुरक्षा के भाव मिले जुले होंगे। राजसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने में मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास एक उदाहरण बनेंगे इसमें दो राय नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का प्रदर्शन हमारी एकता तो दिखाएगा ही, मनोबल भी बढ़ाएगा

► डॉ दिलीप अग्निहोत्री

कोरोना की आपदा से निपटने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन बाकी सब चीजों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता को भी इस लड़ाई में कोरोना को परास्त करने के लिए जरूरी चीज मानते हैं। इस एकता के प्रदर्शन के लिए ही उन्होंने रविवार को रात नौ बजे नौ मिनट तक सभी से अपने द्वार पर प्रकाश करने का आह्वान किया है।

वस्तुतः यह राष्ट्रीय एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। चूंकि, चाहें थाली-घंटी बजाना हो या दीप-टॉर्च जलाना, ऐसी गतिविधियाँ भी इस कोरोना की लड़ाई में देश के मनोबल को ऊंचा रखने की दृष्टि से अत्यंत महत्व रखती हैं और मोदी इस बात को बाखूबी समझते हैं, इसीलिए ऐसा आह्वान कर रहे हैं।

इसके अलावा मोदी ने लॉक डाउन के पालन का भी आह्वान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अकेले नहीं की जा सकती। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यही बात प्रधानमंत्री ने मुखमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कही थी।

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉक डाउन अपरिहार्य है। इसका मखौल बनाने वालों का आचरण अमानवीय है। भारत में जिस प्रकार जनता कर्फ्यू व लॉक डाउन पर अमल हो रहा है, उसके बीच ऐसी कतिपय

घटनाएं आपत्तिजनक हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉक डाउन की सफलता का संकल्प लिया है। उन्होंने देश के लोगों पर विश्वास व्यक्त किया है।

योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। प्रत्येक जिलों में कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं। श्रमिकों व निर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। नरेंद्र मोदी भी कोरोना की सफलता हेतु पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग वार्ता की। उनका मकसद है कि पूरा देश एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करे। उन्होंने सभी से नियमों के अनुपालन का आह्वान किया है। लॉक डाउन, कोरोना टेस्टिंग, कोरोना संदिग्धों का आइसोलेशन व क्वारंटाइन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

दवा, उपकरण इत्यादि की निर्बाध सप्लाई भी सुनिश्चित करनी होगी। अलग कोरोना हॉस्पिटल स्थापित करना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में पहले ही कारगर कदम उठाये हैं। मोदी ने जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित करने का सुझाव दिया। योगी ने जिला व प्रदेश में कार्य ग्रुप बनाये हैं। ऐसी कमेटियां प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। योगी इनके साथ संवाद रखते हैं। इनके

कार्यों की निगरानी करते हैं। आवश्यकतानुसार निर्देश भी देते हैं। संकट की इस घड़ी में प्रत्येक देशवासी को एकजुट रहते हुए कोरोना का मुकाबला करना है।

मोदी ने ठीक कहा कि यह युद्ध से बड़ा संकट है, ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक को स्वयं को बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतनी होंगी। सभी देशवासियों से शान्ति, एकता, सद्भावना और कानून व्यवस्था बनाये रखना चाहिए। मोदी को धर्मगुरुओं का भी आह्वान करना पड़ा। धर्मानुयायियों को कोरोना से निपटने के लिए उठाये जा रहे कदमों का पालन करने के लिए समझाना चाहिए।

सोशल डिस्टेंसिंग को स्वयं की प्रेरणा पर अमल करना चाहिए। इधर योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निपटने के लिए एक कोष की स्थापना के निर्देश दिया। इसका उपयोग मेडिकल कॉलेजों की क्षमता विस्तार, टेस्टिंग लैब्स की स्थापना, पीपीई किट्स का उत्पादन, वेंटिलेटर्स, ट्रिपल लेयर मास्क, आइसोलेशन तथा क्वारंटाइन वार्डों की स्थापना व टेलिमेडिसिन सुविधा के लिए किया जाएगा।

योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उपस्थित अधिकारियों को प्रदेश में वृद्धाश्रम तथा अन्य आश्रय स्थलों का विवरण संकलित करने के निर्देश दिये। योगी ने भी धर्माचार्यों से भूमिका के निर्वाह की अपील की। उन्हें अपने अनुयायियों को लॉक डाउन पर अमल हेतु कहना चाहिए। इसी से समाज का हित होगा। प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित नागरिकों की समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

शेल्टर होम टेण्ट अथवा खुले में न बनाकर किसी भवन में ही बनाया जाएगा। शेल्टर होम्स में भोजन, पेयजल, दवा आदि की पूरी व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रत्येक शेल्टर होम में एक इन्चार्ज नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश के सभी जनपदों में कम्युनिटी किचन का सफल संचालन किया जा रहा है। जरूरतमन्दों को उचित माध्यम से कुकड फूड के पैकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलाधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थ की जारी की गयी रेट लिस्ट से कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण लगा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तबलीगी जमात से सम्बन्धित विदेशियों पर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप एपिडेमिक एक्ट तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इन्हें क्वारेन्टाइन भी किया जाए।

कुल मिलाकर स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस महामारी से निपटने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार का कामकाज अन्य राज्यों के नजीर की तरह है। इसके साथ ही मोदी ने आज जो प्रकाश करने का आह्वान किया है, ये न केवल देशवासियों में एक उत्साह और उल्लास पैदा करेगा बल्कि विश्व को भी इस आपदा के वक़्त हमारी एकता का सन्देश देगा।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

जनता कर्फ्यू : यह कोरोना से बचाव ही नहीं, आपदा में देश की एकजुटता का प्रमाण भी है

► नवोदित सक्तावत

को रोग वायरस के रूप में आज मानवता के समक्ष एक वैश्विक संकट आन खड़ा हुआ है। जहां दुनिया भर के देश इससे जूझ रहे हैं, वहीं भारत में इस वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महामारी के खतरे से बचाव के लिए आज 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। मोदी ने दो दिन पहले राष्ट्री के नाम दिए संदेश में पूरे देश से यह अपील की थी कि 22 मार्च को स्वे च्छा। से सारे बाजार बंद रखे जाएं और लोग अपने घरों में रहें। भीड़ से बचें और किसी भी तरह के संपर्क में ना आए। मोदी की इस अपील का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है।

असल में मोदी यह चाहते हैं कि जब तक कोरोना का कोई सक्षम इलाज ईजाद नहीं हो जाता है, इससे बचाव पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके चलते उन्होंने पूरे देश से स्वे च्छो से बंद रखने का आग्रह किया। इस बात में सार्थकता भी नजर आती है क्योंकि कोरोना का घातक वायरस यदि एक दिन भी इस प्रकार के तमाम तरीकों से संक्रमित नहीं हो पाता है तो यह प्रयास अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होगा।

भारतीय रेलवे ने भी प्रधानमंत्री की मंशा के साथ कंधे से कंधा मिलाया और पूरे देश भर की पैसेंजर ट्रेनों को निरस्तन करने का निर्णय लिया है। ट्रेनों में बड़ी आबादी यात्रा करती है इसलिए संक्रमण का सर्वाधिक खतरा यहीं पर है। इस पर रोक लगाने से संक्रमण को रोका जा सकता

है।

देश के कई शहरों को लॉक डाउन किया जा चुका है। गुजरात के चार शहर पूरी तरह बंद रहेंगे। पंजाब और राजस्थान में लॉकडाउन हो गया है। यह खतरे की तो घड़ी है ही, परीक्षा और धैर्य की भी घड़ी है। इसी दौरान सरकार एवं जनता के आपसी तालमेल का भी पता चल रहा है।

चीन के वुहान से दुनिया भर में पैर पसार चुके घातक कोरोना वायरस की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्वा स्वा स्त्रा संगठन सहित कई देशों व राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हालात गंभीर हैं और इस जानलेवा संक्रमण से बचना चुनौती है। इस वायरस के संक्रमण का आरंभ तो चीन से हुआ लेकिन चीन के अलावा भी इसने कहर बरपाया है।

देश में अभी तक तीन सौ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और छः मौतें हो चुकी हैं। चीन के बाद भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सवा सौ करोड़ की आबादी के बीच इस संक्रामक बीमारी का तेजी से फैलना एक बड़ी आशंका है। इसके चलते भारत सरकार ने हालात को नियंत्रित करने के लिए जी जान लगा दी है।

अधिकांश राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पब, जिम, क्लोब, सार्वजनिक समारोह, शादी समारोह आदि निरस्त कर दिए गए हैं। ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। स्टे शन पर भीड़ हटाने के लिए प्लेनटफार्म टिकट के दाम 10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी

बंद कर दिया गया है।

एक प्रकार से देखा जाए तो बाजारों में सन्नाटा है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन यह सब अहतियात और लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसलिए सरकार के फैसलों का जनता भी भरपूर सहयोग कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बार आईपीएलएल सहित घरेलू स्पर्धाएं भी सुरक्षा के चलते निरस्त कर दी हैं।

जिस तेजी से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला है, उस हिसाब से यह संभव था कि भारत में यह कोहराम मचा देता क्योंकि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हमेशा रहती है। लेकिन सरकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिये कि बहुत कम समय में सरकार ने अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में युद्ध स्तर पर झोंक दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज भी आबादी के मान से देश में संक्रमितों की संख्या कम है और इससे बचने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए हैं। देश भर का एक नंबर भी जारी किया है। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में तो विगत 72 वर्षों से विराट पैमाने पर चले आ रहे होली-रंगपंचमी महोत्सव को भी इस बार निरस्त कर दिया गया। इस आयोजन में लाखों लोग जुटते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जनता भी जागरूक हुई है और सरकार की मंशा के

साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है।

कई राज्यों में 31 मार्च तक स्कूल व कॉलेज बंद हैं। संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी पर्यटक स्थलों, मंदिरों, दफ्तरों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। अनेक राज्यों में भी ऐसी हर जगह को बंद कर दिया गया है जहां अधिक भीड़ जमा हो सकती है। मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु, दिल्ली जैसी जगहों पर प्रशासन ने निजी कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवाएं।

कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी लागू कर दी है। यह अच्छी बात है कि स्थिति की भयावहता को देखते हुए सभी प्रदेश की सरकारें स्वाविवेक से निर्णय ले रही हैं। अभी तक तो भारत में अन्य देशों की तुलना में स्थिति नियंत्रण में ही है। सोशल मीडिया पर भी सरकार नजर रख रही है। भ्रामक सूचना देने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। हालांकि कोरोना का खतरा कब थमेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन परहेज ही सबसे बड़ा इलाज है। इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर सरकार एवं जनता चल रही है। निश्चित ही देश में कोरोना के संक्रमण से आगामी समय में पूरी तरह से निपटा जा सकेगा, यह उम्मीद की जा सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना काल में ममता की संकीर्ण राजनीति का शिकार बंगाल

► डॉ रवि प्रभात

पूरा विश्व कोरोना के भयंकर संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत ने अभी तक अपनी प्रबंधन क्षमता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से कोरोना का डटकर मुकाबला किया है तथा यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत इस व्याधि को नियंत्रित रखने में काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रहा है।

कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिए संघीय प्रणाली वाले भारत में सभी राज्य सरकारों का सक्रिय एवं सकारात्मक रहना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार के साथ-साथ जब तक राज्य सरकारें अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोरोना की इस जंग में अपनी उपयुक्त भूमिका नहीं निभाएंगी तब तक कोरोना का खतरा टलेगा नहीं।

बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का रवैया कोरोना काल में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, जिससे यह लगने लगा है कि कहीं बंगाल कोरोना की इस लड़ाई में कमजोर कड़ी साबित ना हो जाए। यह सर्व विदित है कि ममता बनर्जी ने पिछले सालों में केंद्र की मोदी सरकार के साथ न केवल संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, अपितु असंगत विरोध के चलते संघीय ढांचे पर भी प्रहार करती भी नजर आई हैं।

वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में किसी भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दलगत राजनीति को तिलांजलि देकर राष्ट्रहित में

सहयोगात्मक व सकारात्मक रुख अख्तियार करे, इस संदर्भ में ममता की अमानवीय राजनीति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है।

मार्च माह के आरंभ में जब कोरोना भारत में दस्तक दे चुका था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी होली मंगल मिलन के कार्यक्रम रद्द कर देश के लोगों से यह आह्वान किया था कि होली पर एक साथ इकट्ठे ना हों। परंतु ममता बनर्जी कोरोना वायरस की संवेदनशीलता समझते हुए भी अपनी तुष्टिकरण की राजनीति से बाज नहीं आईं एवं उन्होंने इसे दिल्ली दंगों को छिपाने की साजिश बताकर प्रधानमंत्री की उस संजीदा अपील का उपहास तो किया ही साथ ही लोगों को बड़े आयोजनों के लिए उकसाया भी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था।

विश्व में कोरोना से हो रही तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की, वस्तुतः लॉक डाउन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना संक्रमण की गति को थाम सकता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय देखने में नहीं आया है।

कानून व्यवस्था चूँकि राज्य का विषय है इसलिए लॉकडाउन को लागू कराना तथा उसकी सही अनुपालना कराना यह राज्यों का दायित्व है। निजामुद्दीन मरकज में जमातियों ने जिस तरह लापरवाही बरती इससे देश को कोरोना के बड़े स्तर पर प्रसार के संकट से भी रूबरू होना

पड़ा है।

पुनरापी ममता बनर्जी ने बंगाल में लॉकडाउन का सही अनुपालन कराने के अपने दायित्व में बेहद शिथिलता बरती। ममता बनर्जी ने इसे भी अपने मुस्लिम वोट बैंक समीकरण से जोड़कर देखा तथा मुस्लिमों को शबे बारात मनाने के लिए मजहबी जलसे की अनुमति प्रदान कर पूरे बंगाल को संकट में धकेलने का काम किया। इतना ही नहीं कुछ बाजारों को भी खोलने की अनुमति दे दी, जिससे कोलकाता में राजा बाजार, नारकेल डोगा, टॉप्सिया, मेतियाबुर्ज जैसी जगहों पर सब्जी, मछली, मांस बाजारों एवं बड़ा फूल बाजार में खुलकर लोकडाउन का उल्लंघन हुआ। बिना किसी दूरी का ध्यान रखते हुए खूब भीड़ इकट्ठी हुई। परंतु ममता सरकार ने अपनी आंखें मूंदे रखीं जो कि खुद आपदा को न्योता देने जैसा है।

ममता सरकार ने इतनी भारी चूक लोकडाउन का पालन ना करा के की जिससे खिन्न होकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके कहा कहा कि जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोकडाउन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा पा रहे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए साथ ही उन्होंने राज्य में अर्धसैनिक बलों को बड़े स्तर पर तैनात करने की मांग की। जिससे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है।

ममता सरकार की इस लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी नाराज नजर आया तथा तुरंत कदम उठाते हुए ममता सरकार को लॉकडाउन का पालन कराने की हिदायत दी एवं बरती हुई लापरवाही की रिपोर्ट तलब की। इस प्रसंग से यह बात साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लोकडाउन को राजनीतिक कारणों से गंभीरता से न लेकर बंगाल की जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का निंदनीय काम किया है।

ममता सरकार पर पिछले दिनों कोरोना संक्रमित लोगो

के आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगे हैं जब मृतकों की संख्या 8 बताने के बाद उसे 3 में परिवर्तित कर गया। इसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में टेस्ट न करने के भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा राज्य होने पर भी बंगाल में अभी तक चार हजार के करीब ही टेस्ट किए गए हैं।

जबकि देश के 23 राज्यों में जमातियों द्वारा संक्रमण की घटनाएं हुई हैं उन सभी राज्यों ने जमातियों को दूँड कर उन्हें क्वॉरंटाइन करने एवं टेस्ट करने के कार्य को तीव्रता से किया है। बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में जमाती भागकर राज्य में आए हैं लेकिन ममता सरकार अपने वोट बैंक के नाराज होने के डर से ना उनकी टेस्टिंग करा रही है ना ही उन्हें क्वारंटीन करने पर ध्यान दे रही है।

ममता बनर्जी से जब जमातियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी इसे सांप्रदायिक कहकर टाल दिया। राहुल सिन्हा के आरोपों में अगर एक प्रतिशत भी सच्चाई हुई तो यह आने वाले समय में बेहद खतरनाक हो सकता है।

तमाम अध्ययन इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि लॉकडाउन से देश के गरीब मजदूर तबके को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए का बड़ा आर्थिक पैकेज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से घोषित किया है, परंतु ममता अभी भी अपने राजनीतिक विरोध पर कायम रहते हुए बंगाल के गरीबों के हक पर कुंडली मारकर बैठी हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली 6000 रुपये की सम्मान राशि बंगाल के पंजीकृत पांच लाख से अधिक किसानों तक नहीं पहुंचने नहीं दी जा रही है। जबकि देश के 8 करोड़ से अधिक किसानों को लॉकडाउन होने के बाद ₹2000 की किस्त जारी कर दी गई

है। इसी तरह से आयुष्मान भारत जैसी गरीब कल्याणकारी योजना को भी ममता ने बंगाल में लागू न करके अपनी तुच्छ राजनीति का ही परिचय दिया है, जबकि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने भी तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आयुष्मान भारत योजना को गरीबों के हित में लागू कर दिया है।

इसी प्रकार पिछले दिनों ममता बनर्जी ने पीपीई किट के रंग को लेकर भी बेहद संकीर्ण राजनीति का परिचय देते हुए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था जबकि पीपीई किट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार की जा रही है, जिसमें गुणवत्ता महत्वपूर्ण है उसका रंग कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों ममता दीदी की आदत हर बात को मुस्लिम वोट बैंक की कसौटी पर कसने की हो गई है।

पिछले दिनों यह भी देखने में आया कि बंगाल बेहद बुरी तरह आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। ममता सरकार ने कई क्लबों को एक-एक हजार करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं जबकि इस समय सभी राज्य सरकारें अपने फंड को कोरोना से लड़ने में इस्तेमाल कर रही हैं।

ममता सरकार पर ऐसे भी आरोप लगे हैं कि वह राहत कार्यों में भी राजनीति कर रही है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की जगह अपनी पार्टी के नेताओं को भेजकर

राशन वितरण कराया जा रहा है वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही। बंगाल के राज्यपाल ने राशन वितरण को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी चिंता व्यक्त की है।

कोरोना ने मानवता के समक्ष एक असाधारण संकट खड़ा कर दिया है इससे निबटने के लिए प्रयास भी असाधारण ही करने होंगे। जहां एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि कोरोना से निबटने में केवल सरकार की नहीं अपितु जनता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है वही एक चुनी चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर अपने राजनीतिक दुराग्रहों के चलते घोर लापरवाही बरत रही है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

ममता बनर्जी को यही सलाह है कि इस संकट काल में सबका इतिहास लिखा जा रहा है इसलिए अपनी संकीर्ण राजनीति को परे रखकर बंगाल की संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर कार्य करें। राजनीतिक द्वेष और वोट बैंक की राजनीति करने का यह उपयुक्त समय नहीं, थोड़ी सी भी चूक बड़ा भारी संकट खड़ा कर सकती है, जो अक्षम्य होगा।

(लेखक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में सहायक प्राध्यापक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

तीन मोर्चों पर कोरोना से लड़ रही मोदी सरकार, नागरिकों की भी है बड़ी जिम्मेदारी

► डॉ दिलीप अग्निहोत्री

को रोगा विश्वव्यापी संकट है। इससे प्रभावित देश अपने अपने तरीके से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका सहित कई देशों ने स्वास्थ्य आपात काल लागू किया है। इधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ तीन मोर्चों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्व समुदाय को साझा रणनीति बनाने का सुझाव दिया। यह वादा किया कि भारत इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। दूसरा उन्होंने सार्क देशों का केवल आह्वान ही नहीं किया, बल्कि इस संगठन के सबसे बड़े सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह का जज्बा दिखाया। कहा कि भारत कोरोना से निपटने की तैयारी में सार्क के नेतृत्व हेतु भी तैयार है।

मोदी का तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर है। उन्होंने दवाई, जांच आदि के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। सरकार इसके लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों के साथ भी सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी ने अभिभावक के रूप में भी राष्ट्र ने नाम सन्देश दिया है। विश्व के किसी भी शासक ने ऐसी भावपूर्ण अपील नहीं की है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसी चीजों का विशेष महत्व होता है।

भारतीय संस्कृति में मानवता और वसुधैव कुटुम्बकम् का दर्शन रहा है। इसी के साथ आत्म संयम व कर्तव्य पालन को भी महत्व दिया गया। मोदी के सन्देश में इन्हीं तत्वों का समावेश था। इस बीमारी के बारे में यह जगजाहिर हो गया है कि यह बीमार व्यक्ति के छूने से होती है। इतना ही

नहीं उसके द्वारा छुई गई वस्तुओं से भी संक्रमण हो जाता है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के इलाज के साथ ही भीड़भाड़ न करना, जहां तक संभव हो घर में ही रहना भी अपरिहार्य है। इसी सन्देश को फिलहाल दिनचर्या में उतारने के लिए मोदी ने बाइस मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है।

मोदी ने कहा कि इस दिन आवश्यक सेवाओं वाले लोगों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यथासंभव घरों के अंदर ही रहने से बचाव का तरीका है। मोदी ने कहा कि बाइस मार्च को हमारा आत्म संयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। जनता के लिए जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू होगा।

इतना ही नहीं, मोदी चाहते हैं कि देश कोरोना पीड़ितों का उपचार व सेवा करने वालों के प्रति भी आभार व्यक्त होना चाहिये। बाइस मार्च की शाम पांच बजे डॉक्टरों, चिकित्सा के पेशों में लगे लोगों, साफ सफाई में लगे कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

दरअसल अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई सटीक उपाय नहीं मिला है। न ही कोई टीका विकसित हुआ है। अतः ऐसे सभी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जो जोखिम उठाकर आवश्यक कामों में लगे हैं और इस महामारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं। रविवार को पांच बजे से अपने घर के दरवाजे पर, बालकनी में या खिड़कियों

के सामने खड़े होकर पांच मिनट तक ताली-थाली बजा कर उन लोगों के प्रति कृतज्ञता जताने का आग्रह मोदी ने किया है।

मोदी के इस आग्रह के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन जताया है और इसका पालन करने का संकल्प लिया है, वो दिखाता है कि मोदी के वक्तव्य का जनमानस के बीच गहरा प्रभाव पड़ा है। शायद लोग इस प्रकार के संबोधन की ही अपेक्षा कर रहे थे, जिससे उन्हें हिम्मत और मार्गदर्शन मिले।

इसके पहले मोदी ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क देशों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग संवाद किया। मोदी का यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह बीमारी चीन से फैली है। ऐसे में दक्षिण एशिया के देशों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इसी में सबकी भलाई है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान जैसे देश इस समय भी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसे सद्भावना के प्रयास पसंद भी नहीं आते। जबकि सार्क के अन्य सदस्य देशों ने मोदी के प्रयासों का समर्थन किया है। ये देश सहयोग के लिए तैयार हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मोदी जी के

प्रस्ताव का स्वागत किया। कहा कि नेपाल सार्क सदस्य देशों के साथ मिलकर इस घातक संक्रमण से लड़ने के लिए काम करने को तैयार है।

भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मोद सोलिह, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आदि ने भी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साझा प्रयासों से इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। मोदी ने सार्क सदस्यों को बताया था कि प्रशासन और जनता भी इससे निपटने के लिए अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है। सार्क सदस्यों को मजबूत रणनीति बनानी चाहिए।

स्पष्ट है कि इस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सूझबूझ और तत्परता के साथ काम कर रही है। देशवासियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, संयम और समझदारी के साथ सरकार का सहयोग करना चाहिए। मिलजुलकर के ही इस संकट से लड़ा और जीता जा सकता है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

दिल्ली से मजदूरों के पलायन के लिए जिम्मेदार है केजरीवाल सरकार

► आदर्श तिवारी

को रोगा वायरस से हमारी सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोविड-19 संक्रमण के कारण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण को रोकने का सबसे कारगर उपाय यही है कि लोग एक दूसरे के सम्पर्क में ना आए। भारत सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर प्रभावी कदम उठा रही है।

इस संकट से उबरने के लिए जारी लॉकडाउन से स्वाभाविक है कि प्रत्येक भारतवासी को कोई न कोई असुविधा हो रही होगी, लेकिन उनकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिससे उनको भोजन आदि की कोई असुविधा नहीं हो रही, लेकिन इस देश में करोड़ों ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें इस बन्दी के दौरान हर वस्तु की तंगी हो रही क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो प्रत्येक दिन उतना ही कमा पाता है, जिससे उनकी दो वक्त की दाल-रोटी का प्रबंध हो सके।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ का धन आवंटित किया। इस पूरे बजट को जारी करने का मूल यही था कि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। केंद्र के साथ राज्य सरकारों भी इस महामारी से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन पिछले सप्ताह देश के महानगरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी। गरीब मजदूर कैसे भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। इसका

कारण क्या हो सकता है?

दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वहां प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए कूच कर दिए। यह दिल्ली सरकार की विफलता का ताजा नमूना है। बात यह भी सामने निकलकर आ रही है कि डीटीसी बसों के द्वारा लॉकडाउन के दूसरे दिन से श्रमिकों को यूपी सीमा पर यह कहकर छोड़ा गया कि उन्हें वहां से बस मिल जाएगी।

गत शनिवार को आनंद विहार बस अड्डे से जो तस्वीर आई वह मन को आतंकित करने वाली थी। कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी संख्या में मजदूर घर जाने को विवश हैं। आखिर ऐसी साजिश कौन कर रहा है ?

लॉकडाउन के दौरान डीटीसी बसों को संचालित करने का आदेश किसने दिया था? जब लाखों की संख्या में कामगार पैदल ही घर के लिए निकल गए तब दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री यह बोल रहे कि लोगों की बसों की व्यवस्था की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? गौरतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य एवं रहने की सुविधा मिलेगी फिर वो अपनी जान जोखिम में लेकर बाहर क्यों निकलेगा। दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने के दावे कर रही है किन्तु भारी तादाद में मजदूरों का पलायन यह बताता है कि अरविन्द केजरीवाल की सरकार संकट की इस घड़ी में उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था जिससे भयभीत होकर वह अपने गांवों की तरफ पैदल ही जाने लगे।

जब स्थिति बिगड़ने लगी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसों का प्रबंध करके उन्हें घर पहुंचाने का प्रबंध किया, लेकिन इसी के साथ योगी ने लोगों से यह अपील भी की कि लोग जहाँ हैं वहीं पर रहें। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों आए एक लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य जांच के साथ योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटाइन में रखे जाने के भी आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि जब दिल्ली सरकार कि बसें उत्तर प्रदेश की सीमा पर लोगों को छोड़ने लगीं उसके उपरांत ही ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई। जब देशभर में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर केजरीवाल सरकार की आलोचना होने लगी क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में पलायन दिल्ली से ही हो रहा है और इसमें संशय नहीं है कि अरविन्द केजरीवाल की सरकार श्रमिकों को भरोसे में रखकर उन्हें जरूरी सुविधा मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही है।

गृह मंत्रालय का प्रभावी निर्देश

जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों से मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ कूच करने लगे, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके यह आग्रह किया कि वह प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर तुरंत अपना ध्यान आकृष्ट करें और उनके खाने-पीने एवं रहने का उचित प्रबंध करें।

गृह मंत्रालय ने राज्यों में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों एवं छात्रों की सुविधा के लिए मद्देनजर सभी केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें इस लॉकडाउन के दौरान फंसे सभी प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करने के तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में असंगठित क्षेत्र

के श्रमिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रवासी श्रमिकों के लिए दवा, भोजन, कपड़े एवं रहने की सुविधा के साथ मुफ्त में अनाज की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के साथ ही हाईवे किनारे ही रिलीफ कैंप बनाने की भी बात कही है। अपनी चिट्ठी में गृह सचिव ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने रविवार को पुनः पलायन करते मजदूरों की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को सख्ती से निर्देश दिया है कि वह प्रवासी श्रमिकों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे तथा जिलों एवं राज्यों की सीमाओं को मानवी आवागमन के लिए तुरंत सील करें।

इसके साथ ही जो मजदूर अपने घर के लिए निकल गए हैं, उनको कम से कम 14 दिन के लिए अलग रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस समय सभी काम बंद हैं, लेकिन मंत्रालय ने मजदूरों के वेतन में कोई कटौती न हो, यह भी सुनिश्चित किया है। जो मजदूर किराए के घरों में रहते हैं उनसे मकान मालिक एक महीने न तो किराया मांग सकते हैं और न ही घर खाली करने को बोल सकते हैं। अगर कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय हर स्तर पर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से निजात दिलाने में प्रयासरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं सुझावों को राज्य सरकारें तुरंत अमल में लाएंगीं जिससे प्रवासी श्रमिकों को राहत मिलेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना से लड़ाई में फ़ेक न्यूज़ फैलाने में जुटे वैचारिक गिरोह से सावधान रहने की जरूरत

► अनुराग सिंह

पूरी दुनिया के साथ हमारा देश भी वर्तमान समय में एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। ऐसे मुश्किल दौर में हम सभी को एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हम अपने ज़िम्मेदार होने का सबूत दे सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति अभी नाज़ुक है, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जुटा पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हुआ जा रहा है, दैनिक कामगारों की स्थिति नाज़ुक बनी हुई है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने ही देश में एक तबका फ़ेक न्यूज़ के सहारे सरकार की कोशिशों को विफल करने और इस लड़ाई को और मुश्किल बनाने की कोशिश में लगा है।

फ़ेक न्यूज़ का निर्माण भी एक निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाता है। इसे अपने धर्म, जाति, समुदाय, राजनीतिक दल या फिर किसी भी वर्ग को ध्यान में रखकर गढ़ा जाता है। एक बार जब फ़ेक न्यूज़ अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है तब उसके अगले चरण में उसे आगे प्रेषित करने वाले लोग इसे सच मानकर, बिना इसकी जांच किए आगे भेजने लगते हैं।

दूसरी बात कि एक बेहद सामान्य व्यक्ति इतना जागरूक भी नहीं है कि वो उसके पास आये किसी भी वीडियो, तस्वीर या लिखित सन्देश की जांच करे, ऐसा व्यावहारिक तौर पर संभव भी नहीं है क्योंकि एक दिन में

सैकड़ों संदेश प्राप्त होते हैं।

आज सूचना और तकनीकी के इस युग में बड़ी तीव्रता से वह जल्दी ही बड़े समूह के बीच पहुँच जाता है। इस तरह इसकी शुरुआत जानबूझकर की जाती है और वर्गगत तथा समुदायगत हितों के कारण यह तीव्रता से फैलता चला जाता है। बहुत बार तो यह फ़ेक न्यूज़ हेतु न्यूज़ में भी तब्दील हो जाता है।

मेसाचुसेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 2006 से 2017 के मध्य लगभग 126000 ट्विटर न्यूज़ फीड का अध्ययन किया जो 30 लाख लोगों द्वारा 45 लाख से अधिक बार ट्वीट किया गया था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि ट्विटर पर फ़ेक न्यूज़ फैलने की दर वास्तविक न्यूज़ फैलने की दर से ज्यादा है, खासकर राजनीतिक मामलों में ऐसा अधिक होता है। एक बौद्धिक और तार्किक व्यक्ति के लिए यह वास्तव में चिंतित करने वाली बात है।

अभी कुछ समय पूर्व ही ईरान में एक खबर फैल गयी कि अल्कोहल का सेवन करने से कोरोना से बचा जा सकता है, यह वह समय था जब वहां कोरोना वृद्धि दर काफी तीव्र हो चुकी थी, इस गलत खबर के चक्कर में आकर बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ धो देना पड़ा क्योंकि उन्होंने ज़हरीले मेथेनॉल का सेवन कर लिया।

भारत भी इस फ़ेक न्यूज़ की समस्या से अछूता नहीं रहा, भारत में सरकार को इसका तब शिकार होना पड़ा जब

अमेरिका ने भारत से हाईड्राक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की। देश में यह खबर फैल गयी कि यहाँ अपने पास खुद के लिए दवा नहीं है और हम अपनी दवा अमेरिका को दे रहे हैं जबकि वास्तविकता यह थी कि भारत में कुल 3 करोड़ 28 लाख टेबलेट्स का स्टॉक था तथा हमें आने वाले दिनों में लगभग 1 करोड़ टेबलेट्स की ही आवश्यकता थी।

कुल मिलाकर हमारे पास अगले 6 महीने के लिए पर्याप्त भण्डार था तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं कि अपने पास पड़े हुए अतिरिक्त स्टॉक का लाभ लिया जाए। अतः इस दवा के निर्यात पर लगे हुए प्रतिबन्ध को सरकार ने आंशिक रूप से हटाकर अमेरिका को 35.82 लाख टेबलेट्स निर्यात कर वैश्विक स्तर पर अपने छवि को और भी मजबूत किया।

वर्तमान समय में जब चीन पर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं, हमें अपने आपको मजबूत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम आने वाले समय में बांग्लादेश को 20 लाख, नेपाल और श्रीलंका को 10-10 लाख, भूटान और मालदीव को 2-2 लाख, अफगानिस्तान को 5 लाख टेबलेट्स देने वाले हैं। 13 देशों जिन्हें हम दवा निर्यात करेंगे, की सूची में स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस और सेशेल्स, डोमिनिकन रिपब्लिक भी शामिल है जिसे संभवतः दूसरी क्रिस्त में ये दवाएं भेजी जाएँगी। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दम्पू रवि ने स्वयं यह जानकारी दी कि अतिशय मांग के कारण हम हमारी आवश्यकता से अतिरिक्त टेबलेट्स के निर्यात को मंजूदी देंगे। वास्तविकता यह है और खबर यह बना दी गयी है कि हमारे पास खुद दवा नहीं हैं और बन रहे हैं निर्यातक।

इसी के साथ एक और दिलचस्प खबर जो तुरंत सोशल मीडिया में तैरने लगी वह भी इसीसे जुड़ी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नरेन्द्र मोदी झुक गए और दवा भेज दी, जबकि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप खुद बड़ी शालीनता

से भारत से इस दवा के लिए निवेदन कर रहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि भारत उनकी मदद करेगा क्योंकि दोनों देशों के मध्य रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन ट्रंप के एक सवाल के जवाब में कहे गए शब्दों को धमकी बताते हुए जिस तरह से फेक न्यूज फैलाई गयी, वो शर्मनाक है।

ठीक इसी प्रकार एजेंडा पत्रकारिता करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'द वायर' के संपादक सिद्धार्थ वर्धराजन ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ट्वीट किया कि वे 25 मार्च से 2 अप्रैल तक रामनवमी मेला का आयोजन पहले की तरह ही करवाने वाले हैं, भगवान राम अपने भक्तों को कोरोना वायरस से बचायेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उन्हें इस गलत खबर ट्वीट करने के लिए पहले आगाह किया गया कि वे इसे हटा लें अन्यथा उन पर कानूनी कार्यवाही होगी। उनके न हटाने पर ऐसा ही किया गया। आप ज़रा सोचिए कि ऐसा करने वालों की इसके पीछे क्या मंशा है?

साफ़ तौर पर यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश और लोगों को भ्रमाने का षड्यंत्र है कि सरकार सचेत नहीं है, भीड़ जुटाने को कह रही है। इस ट्वीट से तो ऐसे ही निष्कर्ष निकलते हैं। यदि इस खबर को आधार बनाकर इस बीच वहां भीड़ जुट गयी होती तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होता? कितना नुकसान हो सकता था। इस तरह की अफवाहों का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझने में कोई मुश्किल नहीं है।

जब हमारे प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से लाइट बुझाकर दीप एवं मोमबत्ती जलाकर इस मुश्किल समय में कोरोना के योद्धाओं, चिकित्सकों, सुरक्षाकर्मियों व सफाई कर्मियों का हौसला बुलंद करने को कहा, पूरे देश को एकजुट होने का संदेश देने को कहा, तो कुछ लोग

अचानक से लोड घट जाने से पूरे देश के ग्रिड फेल हो जाने की एक कहानी लेकर आ गए और लोगों से आग्रह करने लगे कि ऐसा बिलकुल भी न करें। जबकि इस दौरान हमें केवल अपने घरों की लाइट ही बुझानी थी, बाकी उपकरण चलते रहते, ऐसे में अचानक से लोड घट नहीं जाता। लेकिन फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों की नजर फ़ैक्ट पर नहीं रहती। उनकी स्पष्ट मंशा होती है कि प्रधानमंत्री के आह्वान को सफल नहीं होने देना है।

इस मुश्किल दौर में जब सरकार की नीतियों व होशियारी से हम अभी बहुत कम नुकसान देख रहे हैं, हमें सरकार का साथ देना चाहिए। यह राजनीति करने का समय

नहीं है, हमें इस समय देश के साथ खड़ा होना है, लेकिन स्पष्ट है कि कुछ तत्त्व इस समय भी अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए फ़ेक न्यूज़ फैलाने में लगे हैं। इस तरह का एजेंडा जो फ़ेक न्यूज़ द्वारा चलाया जा रहा है, वर्तमान समय में न केवल सरकार विरोधी कृत्य है, अपितु देश विरोधी भी है क्योंकि नाज़ुक समय में होने वाले नुकसान की बड़ी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है। हमें ऐसे लोगों व गिरोहों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

क्यों दिल्ली से मुंबई तक पलायन के नाम पर जुटी भीड़ के पीछे साज़िश प्रतीत होती है?

▶ प्रणय कुमार

पहले दिल्ली, अब मुंबई, फिर सूरत, उसके बाद ठाणे, इन सभी जगहों पर लगभग एक जैसे पैटर्न, एक जैसे प्रयोग; एक जैसी बातें, एक जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। सवाल यह भी कि क्या भूख, बेरोजगारी या लाचारी का हौवा खड़ा कर रातों-रात ऐसी भीड़ एकत्रित की जा सकती है? स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी भीड़ के पीछे कुछ संगठनों और चेहरों की भूमिका की संभावनाओं को निराधार और निर्मूल नहीं सिद्ध किया जा सकता। नेपथ्य में दिखता परदे के पीछे का सच भी ऐसी ही किसी साज़िश की ओर इशारा करता है।

कहते हैं कि दिल्ली में तो बक्रायदा घोषणा कर-करके, डीटीसी की बसें उपलब्ध करा-कराकर लोगों को एक निश्चित स्थल पर एकत्रित होने का निर्देश दिया गया। मुंबई में भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के चंद घण्टों बाद हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या यह केवल विनय दुबे जैसे महापंचायत चलाने वाले व्यक्ति के अकेले दम पर संभव था? क्या इसके पीछे निहित राजनीतिक एजेंडे की बू नहीं आती? क्या यह भीड़ चंद घण्टों में एकत्रित की जा सकती थी?

वहाँ एकत्रित भीड़ में से कुछ ने कहा कि उन्हें वहाँ से

ट्रेन से उनके गाँव-घर भेजे जाने की खबर मिली थी। कुछ ने कहा कि उन्हें सूचना दी गई थी कि वहाँ राशन आदि ज़रूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। सवाल यह भी है कि जब बांद्रा से बिहार-उत्तरप्रदेश की ओर कोई ट्रेन जाती ही नहीं तो फिर किसने और क्यों यह अफ़वाह फैलाई तथा उस अफ़वाह पर आसानी से भरोसा कर लेने वाला जत्था कौन-सा था? और लगभग ऐसे ही पैटर्न और प्रयोग ठाणे और सूरत में भी देखने को मिले।

यदि कोई इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भाँप रहा है तो इसमें उसका क्या दोष? क्या जीवन से बढ़कर है भूख और बेरोजगारी? क्या बेरोजगारी कोई रातों-रात दूर होने वाली समस्या है? क्या सालों से दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग इतना भी नहीं कमा और बचा पाते कि एक महीना धीरज और हिम्मत से वहीं रहकर अपना और अपने परिजनों के प्राणों की इस महामारी से रक्षा कर सकें? यदि वे इतना भी नहीं अर्जित कर पाते तो शायद अपना घर-परिवार छोड़कर शहरों का रुख ही नहीं करते, क्योंकि आज गाँवों में भी कृषि-कार्य एवं मवेशी-पालन आदि के लिए दिहाड़ी मजदूरों की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उनकी दैनिक मज़दूरी भी कहीं-कहीं 400-400 रुपए तक पहुँच गई है।

पलायन को केवल भूख और बेरोजगारी से जोड़ना एक सरलीकृत निष्कर्ष होगा। चूंकि बात अलग विषय पर हो रही है, इसलिए यहाँ पलायन के कारणों पर सविस्तार चर्चा करना भी विषयांतर हो जाएगा। ऐसे में यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि यह अनियंत्रित ही नहीं, बल्कि कुछ सीमा तक अराजक भीड़ द्वारा देश को विकास की पटरी से उतारने का कुचक्र है। समय-असमय का ध्यान किए बिना प्रधानमंत्री मोदी और उनके हर निर्णय को विफल करने का षड्यंत्र है।

आप सोचिए कि जब केंद्र और तमाम राज्य सरकारों

भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का न केवल बारंबार आश्वासन दे रही हैं, अपितु उस दिशा में लगातार सक्रिय और सचेष्ट भी दिखाई दे रही हैं, तब ऐसी भगदड़, ऐसी हाय-तौबा का क्या अर्थ है? एक संभावना यह भी है कि राजनीतिक साजिशों से अनजान इस जनसैलाब में कुछ भोले-भाले, अधीर लोग अपने-अपने गाँव महामारी के वाहक बनकर पहुँच जाएं। इनमें से अधिकांश की स्थिति ऐसी होगी कि वे महीना-दो-महीना शहर में रुक सकते हैं। अतः कोई उन्हें समझाए कि अपनी अज्ञानता में वे अपने परिजनों के लिए बीमारी की सौगात लेकर जाना चाहते हैं और कुछ राजनीतिक गिरोहों के शातिर लोग उन्हें अपना राजनीतिक ग्रास बना लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर अभी इन्हें समझा-बुझाकर, शांत कर, परिस्थितियों की भयावहता से परिचित कराने का प्रयास करना ही उपाय है।

विडंबना यह है कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं और वातानुकूलित कक्षों में बैठ गरीबों-मजलूमों की बात करना इस देश के कतिपय नेताओं-बुद्धिजीवियों का फैशनेबल चलन रहा है। समय-असमय नक़ली क्रांति की राग अलापने वाला यह क्रांतिकारी वर्ग/क्लास शायर हो सकता है, लीडर हो सकता है, फिलॉस्फ़र हो सकता है, इंटलैक्चुअल भी हो सकता है, बल्कि और भी बहुत कुछ हो सकता है, पर गरीबों-मजलूमों का, हमारा-आपका, सच्चा हितैषी, हमदर्द और हमसफ़र नहीं हो सकता। वह तो कोई जमीन से निकला; धरातलीय अनुभव, संघर्ष व संस्कारों की आँच में तपा-सच देखने, सच जानने, सच कहने का साहस रखने वाला परिव्राजक सदृश त्यागी व्यक्तित्व ही हो सकता है।

कटु किन्तु सत्य है कि इस देश के बुद्धिजीवियों-पत्रकारों-सरकारों, विशिष्ट समझे जाने वाले स्वयंभू लोगों में भी कई बार ग़ज़ब का दोमुंहापन देखने को मिलता है।

परमुखापेक्षिता और परावलंबिता की संस्कृति ने भारत के गाँवों व आम लोगों को आत्मनिर्भर ही कहाँ रहने दिया और वोट-बैंक को ध्यान में रखकर दी जाने वाली अनुदानों की अनियंत्रित बाढ़ ने भी कोढ़ में खाज का ही काम किया।

खैर, रोग की जड़ तक जाकर भारत सरकार को सोच-विचार के साथ दूरगामी एवं तात्कालिक हितों को साधने वाले निर्णय लेने की जरूरत है। और हर्ष का विषय है कि सरकार कोरोना और उससे उत्पन्न भयावह स्थिति-परिस्थितियों पर पैनी निगाह रख रही है, तेजी से निर्णय ले रही है, उसकी समीक्षा कर रही है और आवश्यक प्रतीत होने पर संशोधन भी कर रही है। उसके द्वारा घोषित राहत पैकेजों में भी सचमुच बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।

सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन एक समाज के रूप में आज हमें भयावह आडंबरों, भावुक अतिवादों और मिथ्या दर्पों से जकड़े हुए समाज के समान व्यवहार करने की बजाय एक परिपक्व और जिम्मेदार समाज के रूप में अपना दायित्व निभाने की आवश्यकता है। भारत और भारतवंशियों ने सदैव ही संकट-काल में अपना सर्वोत्तम दिया है। चंद्र स्वार्थी ताकतों एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहों-षड्यंत्रों को पराजित कर निश्चय ही हम सामूहिक संकल्प, संयम, सहयोग से इस संकट पर भी विजय पाएंगे। कोरोना की इस महामारी से लड़ने में हौसले और धीरज से काम लेते हुए हम दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

एफडीआई नियमों में ताजा बदलाव से होगी भारतीय हितधारकों की रक्षा

▶ सतीश सिंह

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में 18 अप्रैल से बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों से भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी पड़ोसी देश को भारत में निवेश करने के लिए भारतीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह नियम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के निवेश पर लागू होगा। पहले ऐसी पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर थी। अब यह चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान पर भी लागू होगा।

अगर सरकार एफडीआई के नियमों में बदलाव नहीं करती तो चीन भारतीय कंपनियों का शेयर खरीदकर उनका मालिकाना हक हासिल कर सकता था। हाल में चीन के सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1.01 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी थी, जिससे भारतीय सरकार को एफडीआई के नियमों पर पुनर्विचार करने का मौका मिला।

गौरतलब है कि नये नियमों के मुताबिक भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि भारत की सीमा से लगे देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे तो भी निवेश के लिये सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

भारतीय कंपनी में यदि एफडीआई से किसी कंपनी का मालिकाना हक बदलता है और ऐसे निवेश में लाभार्थी भारत से सीमा साझा करने वाले देशों में होता है या वहां का नागरिक होता है, तो भी उसे सरकार से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी।

नये नियमों के मुताबिक कोई भी अनिवासी निकाय या कंपनी एफडीआई नीति के अंतर्गत भारत में निवेश कर सकती है। अनिवासी निकाय द्वारा केवल उन क्षेत्रों या गतिविधियों में निवेश करने की मनाही होगी, जो प्रतिबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में लॉटरी, जुआ या सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, सिगार, चुर्रूट, तंबाकू वाले सिगरेट आदि क्षेत्रों में विदेशी निवेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वैसे देश की कंपनी या निवेशक, जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है, भी भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं।

कोरोना वायरस के कारण विश्व के अधिकांश देशों के शेयर बाजार ध्वस्त हो गये हैं। कंपनियों के शेयर की कीमत कम होने का फायदा चीन जैसा अवसरवादी देश उठा सकता है। इस मामले में वस्तुस्थिति को समझने के लिए शेयर और शेयर बाजार के परिचालन को समझना जरूरी है। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को शेयर ब्रोकर की मदद से खरीदा व बेचा जाता है यानी कंपनियों के हिस्सों की

खरीद-बिक्री की जाती है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) नाम से दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। शेयर बाजार में बांड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव भी खरीदे एवं बेचे जाते हैं।

कोई भी सूचीबद्ध कंपनी पूंजी उगाहने के लिये शेयर जारी करती है। कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को शेयर खरीदना होता है। जितना निवेशक शेयर खरीदते हैं, उतना उसका कंपनी पर मालिकाना हक हो जाता है। निवेशक अपने हिस्से के शेयर को ब्रोकर की मदद से शेयर बाजार में कभी भी बेच सकते हैं। ब्रोकर इस काम के एवज में निवेशकों से कुछ शुल्क लेते हैं। जब शेयर जारी की जाती है तो शेयर किसी व्यक्ति या समूह को कितना देना है का निर्णय कंपनी का होता है।

शेयर बाजार में खुद को सूचीबद्ध कराने के लिये कंपनी को शेयर बाजार से लिखित करारनामा करना होता है। इसके बाद कंपनी सेबी के पास वांछित दस्तावेजों को जमा करती है, जिसकी सेबी जांच करता है। जांच में सूचना सही पाई जाने पर आवेदन के आधार पर कंपनी को बीएसई या एनएसई में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। तदुपरांत, कंपनी को समय-समय पर अपनी आर्थिक गतिविधियों के बारे में सेबी को जानकारी देनी होती है, ताकि निवेशकों का हित प्रभावित नहीं हो।

भारत-चीन आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिषद के आकलन के अनुसार, चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में लगभग 4 अरब डॉलर निवेश किया है। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच भारत में चीन के निवेशकों ने 2.34 अरब डॉलर यानी 14,846 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि समान अवधि में बांग्लादेश ने 48 लाख

रुपए, नेपाल ने 18.18 करोड़ रुपए, म्यांमार ने 35.78 करोड़ रुपए और अफगानिस्तान ने 16.42 करोड़ रुपए का निवेश भारत में किया है, जबकि पाकिस्तान और भूटान ने इस अवधि में भारत में कोई निवेश नहीं किया है।

गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि में भारत में कुल 36.77 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, जो उसके पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा था। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर किसी देश की कंपनी या उस देश का निवेशक किसी देश में या वहाँ की किसी कंपनी में निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं।

कोरोना वायरस के कारण भारत समेत कई दूसरे देशों ने एफडीआई के नियमों को सख्त बनाया है। यूरोपीय संघ ने भी हाल ही में सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए एफडीआई नियमों को सख्त बनाया है। अमेरिका भी चीन से आने वाले निवेशों की कड़ाई से जांच-पड़ताल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बीते दिनों एफडीआई के नियमों को सख्त बनाया था।

कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए चीन भारत की कंपनियों में निवेश करके उनका अधिग्रहण कर सकता है, क्योंकि देशव्यापी आर्थिक गतिविधि बंद होने के कारण भारतीय कंपनियों के शेयर कमजोर हो रहे हैं। फिलवक्त, चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में उसके नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव एक कारगर कदम है।

**(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं।
ये उनके निजी विचार हैं।)**

कोरोना आपदा ने समझाया कि क्यों जरूरी है नागरिकों का डाटाबेस

► रमेश कुमार दुबे

यदि मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत नकदी हस्तान्तरण की बिचौलियामुक्त व्यवस्था न की होती तो राहत सामग्री बांटने के नाम पर आज देश भर के ग्राम प्रधान, लेखपाल, पार्षद मलाई काट रहे होते। यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का कथन प्रासंगिक है “दिल्ली से एक रूपया भेजते हैं तो गांवों तक 15 पैसे पहुंचता है 85 पैसा बिचौलिए हड़प लेते हैं।” यदि देश की गरीबी, बेकारी, असमानता, नक्स लवाद, अग्रवाद की जड़ तलाशी जाए तो वह इसी संगठित लूट में ही मिलेगी।

इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी एक ऐसी बिचौलियामुक्त व्यवस्था बनाने में जुट गए जिसमें दिल्लीत से भेजा गया रूपया बिना किसी बंदरबाट के सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे। इस दिशा में पहला ठोस कदम था सभी भारतीयों का बैंक खाता। इसके लिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत 38 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इन नए बैंक खातों में से 53 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए। विश्वा बैंक ने इस मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे देश की करोड़ों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से जुड़ने का मौका मिला।

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी पाटने का काम किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के

तहत देश में जितने बैंक खाते खोले गए उसमें से 58 प्रतिशत ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में स्थित बैंक शाखाओं में खुले। इन सबका नतीजा यह हुआ कि आज 80 प्रतिशत से अधिक वयस्कों के पास बैंक खाता है जबकि 2014 में यह अनुपात महज 50 प्रतिशत था।

इसी तरह पूरे देश में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, स्मार्ट फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ने 2015 में डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किया। इसका उद्देश्य हर स्तर पर कागज रहित प्रक्रिया को अपनाता कि बिचौलियों की समानांतर सत्ता खत्म हो जाए। सरकार डिजिटल इंडिया को सूचना प्रौद्योगिकी का बहुआयामी हथियार बना रही है।

डिजिटल क्रांति का ही नतीजा है कि तेज रफ्तार वाला इंटरनेट, 4 जी स्मार्ट फोन और कमोवेश हरेक विषय पर डिजिटल सामग्री अब बेहद कम दामों पर सबके लिए सुलभ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेल फोन बाजार भारत में है। इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाकर समाज के कमजोर वर्ग अपने को सशक्त बना रहे हैं।

कोरोना आपदा ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की प्रासंगिकता को एक बार फिर उजागर कर दिया। यदि केंद्र व राज्य सरकारों के पास जनसंख्याक संबंधी प्रामाणिक डाटाबेस होता तो उसी आधार पर सरकारें संक्रमण की जांच कर पातीं और आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों तक

तुरंत मदद पहुंचा देतीं।

भारत के संदर्भ में सबसे दुर्भाग्यशपूर्ण स्थिति यह है कि यहां की आबादी का कोई डाटाबेस नहीं है जिससे यह नहीं पता चल पाता है कि कौन देश में आ रहा है और कौन जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के नागरिक बन चुके हैं। इसी का अनुसरण म्यांममार के रोहिंग्याल शरणार्थी कर रहे हैं।

एनपीआर पर देश के कई शहरों में हिंसा करने और महीनों तक सड़क जाम करने वाले धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार क्यार यह बताएंगे कि निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात में दुनिया के कई देशों से आए लोगों की जानकारी क्यों छिपाई गई? यदि जमात के लोगों से देश भर में कोरोना संक्रमण न फैलता तो देश यह जान ही न पाता कि दुनिया के किन-किन देशों से कितने लोग जमात में शामिल हुए।

स्पोष्टक है, कोरोना संकट को देखते हुए भले ही सरकार ने जनगणना 2021 और एनपीआर तैयार करने के कार्य को

अगले आदेश तक स्थगित कर दिया हो लेकिन एनपीआर और एनआरसी की जरूरत को झुठलाया नहीं जा सकता। एनपीआर डाटा बेस में जनसांख्याकी एवं बायोमेट्रिक जानकारी रहेगी। वैसे निवासी जो छह माह या उससे ज्यादा समय से किसी क्षेत्र में रह रहे हों उनके लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा।

एनपीआर का उद्देश्य है देश के सभी नागरिकों की पहचान को व्यापक डाटाबेस के साथ जोड़ा जाए ताकि सरकारी योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इससे आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ एनपीआर से आपदा के समय प्रभावित व्यक्तियों की ट्रैकिंग और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम आसान हो जाएगा। एनपीआर के यही आंकड़े आगे चलकर एनआरसी का आधार बनेंगे।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव से बची रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

► प्रह्लाद सबनानी

दे श की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि अर्थव्यवस्था के बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और सुधार के संकेत अब साफ़ दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने उस समय सुधरती वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया था। जनवरी 2020 में क्रय विनिर्माण सूचकांक (PMI) में जो उछाल आया है वैसा पिछले 8 सालों में देखने में नहीं आया है।

सरकार राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन में 102 लाख करोड़ रुपए, अगले 5 साल में, खर्च करने जा रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 47,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो गया है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की रेटिंग को कम नहीं किया है। इनके अनुसार देश की विकास दर कम भले हुई हो, परंतु यह अभी भी औसत दर से ज्यादा ही है। एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार और राजनैतिक स्थिरता को भी मजबूत बताया है।

विदेशी निवेश भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। औसतन 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्रति माह हो रहा है। यह तब है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी छाई हुई है। कभी भी भारत में इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रहा है। यह विश्वास के चलते ही हो पा रहा है।

बजटीय घाटे को भी नियंत्रण में रखने का प्रयास केंद्र

सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। GST का कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह लगातार पिछले चार माह के दौरान एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। मुद्रा स्फीति हाल ही में थोड़ी बढ़ी जरूर है परंतु फिर भी नियंत्रण में ही बनी हुई है। मुद्रा का प्रसार भी लगभग 10 से 11 प्रतिशत पर नियंत्रण में है। जबकि पिछले दशक के प्रारम्भ में यह 13 से 15 प्रतिशत के बीच रहता था। मौद्रिक नीति में भी स्थिरता बनी हुई है।

इन सभी चीजों को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं देशी निवेशक सोच रहा है कि मैं भी भारत में अपना निवेश बढ़ाऊँ और भारत की तरक्की में भागीदार बनूँ इसलिए भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार हो रहे उक्त वर्णित सकारात्मक घटनाओं के चलते पूरे विश्व, विशेष रूप से चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना वाइरस नामक बीमारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था तो विपरीत रूप से प्रभावित होगी लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। परंतु, इसे एक अवसर के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि चीन में उद्योग बंद कर दिए गए हैं और अभी तक कई देश चीन से ही वस्तुओं का आयात कर रहे थे।

अब जब चीन से माल निकलेगा ही नहीं तो ये देश भारत एवं अन्य देशों की ओर रूख कर सकते हैं। भारत

यदि चौकन्ना रहता है तो उन वस्तुओं का निर्यात भारत से बढ़ाया जा सकता है जिन वस्तुओं का निर्यात चीन से अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए तुरंत ही कई निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है और इन सम्बंधित उद्योगों को समस्त प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपना निर्यात भारत से बढ़ा सकें।

भारत में आज छोटी से बड़ी हर प्रकार की वस्तु निर्मित हो रही है। बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी कम्पनियाँ यहाँ पूर्व में ही स्थापित हैं। इन देशों के अपने उपभोग की पूर्ति भारत में स्थापित कम्पनियों से की जा सकती है। यह शायद होता भी दिख रहा है क्योंकि आईएचएस मार्केट इंडिया सेवा व्यापार गतिविधि इंडेक्स जो जनवरी 2020 में 55.5 अंको पर था, वह फ़रवरी 2020 में बढ़कर 57.3 अंको पर आ गया है। वर्ष जनवरी 2013 के बाद की यह सबसे अधिक वृद्धि मानी जा रही है और विदेशों से प्राप्त निर्यात ऑर्डर को इस वृद्धि के लिए मुख्य कारण माना जा रहा है।

भारत में केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि संस्थानों द्वारा हाल ही में आर्थिक क्षेत्र से सम्बंधित लिए गए निर्णयों का असर भी शीघ्र ही अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगेगा तब आर्थिक गतिविधियाँ और आगे बढ़ेंगी। बैंकों के पास जमा राशियाँ पड़ी हुई हैं जिन्हें ऋण का उठाव नहीं होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा करना पड़ रहा है। अतः ब्याज दरें लगातार कम की जा रही हैं, इसका लाभ भी धीरे धीरे उपभोक्ताओं को मिलेगा।

देश में सरकारी क्षेत्र के 13/14 बैंक हानि दर्शा रहे थे, इनमे से कई बैंक अब लाभ की स्थिति में आ गए हैं। शेष बैंक भी शीघ्र ही लाभ की स्थिति में आ जाएँ ऐसा प्रयास सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है।

भारत में विकास दर को 8 से 9 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता मौजूद है परंतु जब कई अन्य देशों में ऋणात्मक

विकास दर आ गई है तो भारत की विकास दर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में 5-5.5 प्रतिशत की विकास दर भी अच्छी ही कही जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का विश्वास बना हुआ है तभी तो देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार भारत पर अपना विश्वास बनाए हुए है।

भारतियों में अधिक पैसा कमाने की एवं नवोन्मेष की भूख है। भारतियों की इस प्रवृत्ति के चलते देश में आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए लगातार कई प्रयास भी कर रही है।

अब देश में कर की दरों को 10-30 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है जो विश्व में तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसीलिए कर अपवंचन भी कम हुआ है। लिहाजा लोगों में अब कर देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उद्यमिता की भूख भी भारतियों में अब बढ़ रही है। लोग बचत से पोर्टफ़ोलीओ (निवेश) की ओर बढ़ रहे हैं। टैक्स के दरों को ठीक किया गया है। प्रोत्साहन हटाकर करों की दरों को कम किया जा रहा है। ताकि लोग खर्च कर सकें। यह भी बदलाव हो रहा है।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने से भी विदेशी निवेशकों का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग आँकते समय इन पैरामीटर पर विशेष ध्यान देती हैं। हालाँकि पूँजीगत निवेश बढ़ाने के लिए यदि राजकोषीय घाटे का इस्तेमाल किया जाता है तो यह इतना बुरा भी नहीं है। हमारे देश के पास 47,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, अतः सरकार के पास पूँजीगत खर्चें बढ़ाने का मौक़ा उपलब्ध है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

कोरोना राहत पैकेज : लॉकडाउन में गरीबों और अर्थव्यवस्था के हितों को सुरक्षित रखने की पहल

► सतीश सिंह

को रोग वायरस मानव अस्तित्व के लिये आज एक बड़ा खतरा बन गया है, जिससे बचने के उपाय फिलहाल बहुत ही कम दिख रहे हैं। सुधारात्मक उपायों को देर से अमलीजामा पहनाने वाले देशों को धीरे-धीरे यह अपनी चपेट में ले रहा है। सुधारात्मक उपाय नहीं करने पर इसका प्रकोप क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। पहले चरण में यह लोगों को गंभीर नहीं लगता है, लेकिन दूसरे चरण से यह लोगों के प्राणों को लीलने लगता है। नहीं चेतने पर तीसरे चरण में इसका फैलाव समुदाय में हो जाता है और यह फिर यह थोक में लोगों की जान लेता है। तदुपरांत, यह बेकाबू हो जाता है, जिसे रोकना मुमकिन नहीं होता है।

चूँकि, इस रोग की कोई दवा नहीं है। इसलिये, इसके रोकथाम के लिये जरूरी है कि संभावित मरीजों की अधिक-से-अधिक संख्या में टेस्ट किया जाये, ताकि कोरोना से संक्रमित लोगों को अविलम्ब 14 दिनों के क्वारंटाईन में भेजा जाये। इस तरीके से ही लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस अभी दूसरे चरण में है। इसपर काबू पाने के लिये देशव्यापी 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसकी मियाद 14 अप्रैल को खत्म होगी।

लॉकडाउन में निर्माण और अन्य गतिविधियों के ठप्प पड़ने के कारण मजदूरों व अन्य कामगारों के लिये

रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को अपने गाँव लौटना पड़ा है। हजारों की संख्या में मजदूर एवं कामगार जगह-जगह फंसे हुए भी हैं।

कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देने की घोषणा की। सरकार की कोशिश है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे। इस योजना के तहत डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मचारियों आदि का 50 लाख का बीमा किया जायेगा, क्योंकि यह वर्ग अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं।

लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले तीन महीनों तक 5 किलो गेहूँ या चावल और दाल मुफ्त देने का प्रस्ताव है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2 हजार रुपये की किस्त 8.7 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले सप्ताह में अंतरित की जायेगी। मनरेगा के तहत दी जा रही मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन किया गया है, ताकि मजदूरों को आर्थिक परेशानी का कम सामना करना पड़े। बुजुर्ग, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को आगामी 3 महीनों तक एक हजार रुपये देने की भी बात कही गई है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीनों तक मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जायेगा। बीस करोड़ महिला

जनधन खाताधारकों के खातों में अगले तीन महीनों तक हर महीने 500 रुपये जमा किये जायेंगे, ताकि वे मुश्किल वक्त का सामना कर सकें।

कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते से 75 प्रतिशत या 3 महीनों के वेतन के बराबर पैसे की निकासी कर सकेंगे, जिसे उन्हें वापिस नहीं जमा करना होगा। इससे एक बड़े वर्ग को आर्थिक मदद मिलेगी।

महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह को अब 20 लाख रुपये तक ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जायेगा, जिससे स्व-रोजगार का दायरा व्यापक होगा। पंद्रह हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों या कामगारों का भविष्य निधि अंशदान अगले तीन महीनों तक सरकार देगी। निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ पंजीकृत कामगारों को आर्थिक मदद देने के लिये 31,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके पहले 24 मार्च को भी सरकार ने एटीएम शुल्क एवं खातों के न्यूनतम बैलेंस को खत्म कर और आयकर व जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ाकर लोगों के घाव पर कुछ मरहम लगाया था।

आर्थिक मोर्चे पर कारोबारियों और आमजनों को राहत देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च 2020 को मौद्रिक समीक्षा के दौरान सभी मियादी ऋणों पर क्रिस्त एवं ब्याज की चुकौती में 3 महीने की छूट दी है। वर्किंग कैपिटल के ऋण की ब्याज अदायगी में भी 3 महीनों की छूट दी गई है।

कोरोना वायरस के कारण कारोबारी एवं आमजन फिलवक्त बैंकों से लिये ऋण की क्रिस्त एवं ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। इससे बैंकों के ऋण भुगतान करने में चूक की आशंका बढ़ गई थी। रिजर्व बैंक के ताजा फैसले से तीन

महीनों तक क्रिस्त एवं ब्याज ऋण खाते में नहीं जमा करने से वह गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) नहीं होगा और न ही इसके लिये कोई रेटिंग एजेंसी बैंकों की रेटिंग को कम करेगी। कारोबारियों को सस्ती दर पर ऋण मिल सके, इसके लिये केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को 75 बेसिस पॉइंट कम किया है, जिससे यह 5.15 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई है। इससे ऋण के क्रिस्तों में कमी आयेगी।

संवाधिक तरलता अनुपात यानी सीआरआर को भी 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे बैंकिंग प्रणाली में 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी का प्रवाह होगा। सस्ती पूँजी उपलब्ध होने से बैंक सस्ती दर पर कारोबारियों और आमजनों को ऋण मुहैया करा सकेंगे। केंद्रीय बैंक की कोशिश है कि प्रणाली में नकदी की कमी नहीं हो। रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कहा है कि जरूरतमंदों को नकदी मुहैया कराना सुनिश्चित करें, ताकि अर्थव्यवस्था और आमजन को मौजूदा संकट से बाहर निकलने में आसानी हो।

कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस के कारण जब आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप्प पड़ चुकी हैं, ऐसे में सरकार द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपये की मदद की घोषणा करने और केंद्रीय बैंक द्वारा कारोबारियों और आमजन को राहत देने के लिये रेपो दर में कटौती करने, तीन महीनों के लिये क्रिस्त एवं ब्याज की चुकौती में छूट देने, बैंकिंग प्रणाली में लाखों करोड़ रुपये डालने आदि से कमजोर तबके, मध्यम वर्ग और कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है, इस आपदा से देश जल्द ही उबर जाएगा।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

Mamata plays politics of pandemic

▶ **Dr. Anirban Ganguly**

One of the cardinal principles of the fight against Covid-19 worldwide is the need for transparency. Besides Testing, Tracing and Treating, Transparency is the fourth pillar which sustains the struggle against the pandemic. Both India and South Korea continue to do well in this battle primarily because their respective leaders have insisted on transparency. From the word go, Prime Minister Narendra Modi has ensured that the concerned departments, ministries and institutions adhere to this principle. His vision is clear; the fight against Covid-19 has to succeed through peoples' participation—Jan Bhagidaari—with each citizen sensing that they are part of this herculean effort at warding off the virus. With a detailed and regular briefing, continuous flow of information, this approach is evident in the manner the Modi government has approached the issue. Almost all other states have adhered to this principle of transparency. The practice of giving out the exact number of those afflicted, the actual number

of those dying and the daily number of increase and of those cured are regularly and in great detail shared with the people and the media. The main purpose of this is to avoid giving rise to collective panic, allow the tracking of the state's progress in handling the pandemic and to ensure that a collective will is sustained in wanting to overcome it. The only state government, which has resolutely refused to adhere to this principle is the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress government in West Bengal.

The politics of pandemic now being played out in West Bengal by the ruling Trinamool Congress has the following dimensions to it: suppression of data on actual tests done, its results, actual number of those afflicted, those dead from the virus and the actual numbers of those infected in the districts, inter ministerial and departmental discrepancy in data released, deliberate laxity in enforcing lockdown in the first 21 days, especially in those areas of Kolkata and state that are minority dominated, refusal to disclose

the number of those infected because of the Nizamuddin Markaz episode, refusal to ensure proper protective equipment for doctors and healthcare workers at the frontline. Such a callous attitude has led to patients being admitted to general wards and spreading the infection, unclear protocol followed on the disposal of the dead, unclear network of quarantine centres, setting up a committee of doctors who are empowered to “audit the dead”, having the sole authority to decide on whether a particular patient died of corona, preventing the dissemination of authentic information, irregularity in the distribution of ration through PDS. This has led to a number of protests and clashes between people and the police across the state, and targeting of Members of Parliament from Opposition parties particularly the BJP, since it has the largest and active posse of MPs, by preventing them from moving around their constituency for relief distribution. Jalpaiguri Member of Parliament, Jayanta Roy has been forced into a false quarantine for 14 days, while the same is being attempted against Sukanta Majumdar, MP from Balurghat. Member of Parliament from Alipurduar, John Barla too, was obstructed while he was

trying providing relief to his constituents, who are primarily tea garden workers. Thus, the Mamata Banerjee government is not only displaying inconsistencies in tackling the pandemic, it is also displaying a complete lack of a democratic spirit.

This week a group of “non-resident Bengali physicians, health scientists, and health care providers” from West Bengal, who are now spread across the world in leading healthcare institutions, in an open letter to Mamata Banerjee, has referred to the situation in the state as “particularly grave” and pointed at “two specific issues” that are most disturbing: “1) The gross-under testing in West Bengal, and 2) the misreporting of data on the cause of death of Covid-19 patients.” The group, which had as signatories experts from universities of California, Michigan, UCLA Fielding School of Public Health, Stanford University, Johns Hopkins University and Leibniz Institute of Aging among others, clearly stated that there was “evidence that mortality data in Covid-19 patients emerging from West Bengal” were being misreported or not fully reported and that, more crucially, “deaths due to Covid-19 are being misclassified on death certificates as deaths due to a comorbid condition or organ failure...”

Many recall Mamata's approach to the dengue epidemic that had struck West Bengal in 2018 and had led to a number of deaths. A number of doctors across the state had then complained of being coerced into not citing the cause of death as dengue. Being opaque with health data is the TMC's public health policy.

Earlier this month, Mamata Banerjee had formed, with much fanfare, a "global advisory" group headed by Nobel Laureate Abhijit Banerjee to advise her on the pandemic. Except for one televised meeting with Prof Banerjee, there has been no meeting of the group, though a lot has been spent on publicising it. The doctors' committee formed by her to "audit" the deaths, interestingly, does not have pulmonologists, epidemiologists and virologists, all specialist that are needed for the treatment of corona. Instead the doctor who heads it, Abhijit Chowdhury, is a hepatologist, with no known expertise in handling SARS diseases.

Mamata and her ministers have repeatedly claimed that her government has distributed over 4 lakh PPEs across the state, and yet everyday reports of doctors and nurses contracting the infection in main hospitals in the state surface and associations of doctors

repeatedly express public concern and indignation at these protective equipment not reaching them. The resident doctors of the Medical College of Kolkata, have pointed at the "gross mismanagement in the handling (testing, contact tracing, etc) of Covid-19 suspected healthcare workers" and lamented that "the ratio of 3 patients to 11 HCW affected" indicated "enormous callousness on the part of the authorities to set up any form of protection, testing facilities for those of us at the highest risk." Terming it a "suicide mission" they expressed their inability to continue working until their demands especially with regard to PPE, mass testing, quarantine and treatment were met.

The Chief Minister remains unfazed. In fact, a joint letter issued by a host of medical forums in the state with the Indian Medical Association, which has as its president Dr Santanu Sen, TMC's Rajya Sabha MP, in the lead asked the Chief Minister to, among other things, ensure the safety and security of all frontline healthcare providers and demanded opening of more testing centres and issuing of death certificates following ICMR guidelines. The Chief Minister, who holds charge of the health

department as well, has, instead of responding to these demands, blamed the Modi government and has repeatedly tried to shift attention from her own ineptitude and mismanagement.

By refusing to come clear on the impact of the Tablighi Jamaat on the spread of the virus in the state, by repeatedly naming all attempts to make her accountable on this count as “communal”, she has also furthered the agenda of her appeasement politics in this fight against corona.

Unlike neighbouring Assam where the government has clearly indicated the effects of Nizamuddin on spread of the infection, Mamata continues to suppress Tablighi data. As of now she is misleading, mis-reporting and mis-handling West Bengal’s fight against corona.

(This Article was first published in Sunday Guardian.)



(The writer is Director, Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, New Delhi, views expressed are his own)

Published By:

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

  **@spmrfoundation**

Phone:011-23005850